● वर्ष-5

● अंक-296

रायपुर, बुधवार
29 जुलाई 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> मील का पत्थर साबित होगा ...

पेपर लीक पर लोकसभा में चर्चा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा-

कांग्रेस राज में लीक होते रहे पेपर, हमने बनाया फुलप्रूफ सिस्टम

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान कहा कि यह विधेयक वर्ष 2024 में लाए गए पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अधिनियम में संशोधन है। उन्होंने कहा कि यह कानून भी मौजूदा सरकार ही लेकर आई थी और स्वतंत्र भारत के इतिहास में अपनी तरह का पहला कानून था। पहले लाया गया कानून और अब प्रस्तुत किया गया संशोधन, दोनों ही छात्रों और युवाओं के हितों की रक्षा के प्रति सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प की भी पुनर्पुष्टि है कि भारत के बच्चों के भविष्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से यह संशोधन विधेयक भारतीय संसद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होने वाला कानून है।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस काल में अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग परीक्षाओं में पेपर लीक होते रहे, लेकिन शायद उस तरह की कार्यवाही नहीं की गई जैसी अब की जा रही है। उन्होंने 2009 में रेलवे भर्ती पेपर लीक से 2012 के एम्स एंट्रेस पेपर लीक तक, कांग्रेस काल में हुए पेपर लीक गिनाए और कहा कि इसीलिए सोचा गया कि अब इसे लेकर एक फुलप्रूफ सिस्टम बनाया जाए।

भारत में अभी चार प्रमुख परीक्षा एजेंसियां हैं। 1992 में जब सरकार कांग्रेस की थी, एक कमेटी ने सुझाव दिया था केंद्रीय परीक्षा कमेटी के गठन का 2010 में भी एक कमेटी ने ऐसा ही सुझाव दिया था। पहली बार 2024 में यह बिल लाया गया, जून 2024 में लागू किया गया। इस विधेयक के जो मूल उद्देश्य थे, वह परीक्षा में पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करना था। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें 2024 के बिल को और मजबूत करने की जरूरत है, हम इसी कानून में संशोधन के लिए बिल लाए हैं।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार पेपर लीक मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए

स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान इस संशोधन विधेयक के जरिए कर रही है। पूरी जांच दो महीने के भीतर पूरी करने की समयसीमा तय की गई है, जबकि इसके बाद ट्रायल कोर्ट में तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया जाएगा। घटना होने से लेकर अंतिम निर्णय आने तक पूरे मामले के निपटारे में पांच महीने से अधिक समय नहीं लगेगा। यदि कोई पक्ष फैसले के खिलाफ अपील करना चाहता है, तो उसे 30 दिनों के भीतर अपील करनी होगी। साथ ही, ऐसे मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में डबल बेंच से नीचे नहीं होगी।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार एक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आई है और उसकी प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विधेयक पेश करने के साथ ही कानून मंत्रालय ने स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठित और राधाकृष्णन समिति की 46 प्रमुख सिफारिशों में से 35 को पहले ही लागू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा पूरी तरह ईमानदार है और यह संशोधन भी उसी दिशा में किया गया एक गंभीर प्रयास है। उनका कहना था कि इन प्रस्तावों पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और यदि कोई विरोध करता है, तो उस पर देश की जनता सवाल उठाएगी।

विपक्ष को चर्चा के लिए जितना वक्त चाहिए, सरकार तैयार : रिजिजू

विधेयक की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने संसद में चर्चा का दायरा और समय बढ़ाने की घोषणा की है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और एनसीपी समेत तमाम प्रमुख विपक्षी दलों के चीफ व्हिप और नेताओं से बातचीत की है।

किरेन रिजिजू ने कहा शुरुआत में इस बिल पर 6 घंटे की चर्चा तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 8 घंटे करने पर सहमति बनी है। यदि विपक्ष को और अधिक समय चाहिए, तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। हम इस पर 10 घंटे तक भी चर्चा कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, ताकि एक मजबूत और असरदार कानून सामने आ सके।

पेपर लीक संशोधन विधेयक पर गौरव गोगोई का सरकार पर हमला

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में चर्चा के दौरान सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने असम में आई बाढ़ और उसमें 70 लोगों की मौत का जिक्र करते हुए राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग भी उठाई।पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर बोलते हुए गोगोई ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है और यह विधेयक केवल दिखावा करने के लिए लाया गया है। गोगोई ने कहा कि सरकार का यह कदम सिर्फ एक आंखों में धूल झोंकने जैसा प्रयास है। इस विधेयक से परीक्षा प्रणाली में वास्तविक सुधार नहीं होगा और सरकार को इस मुद्दे पर ठोस तथा प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, 2024 के नीट पेपर लीक मामले में आरोपपत्र दाखिल किए गए 46 आरोपियों में से 44 को जमानत मिल चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले के कथित मास्टरमाइंड संजीव मुखिया 11 महीने तक फरार रहा और गिरफ्तारी के बाद उसे भी जमानत मिल गई। इसके अलावा अमित कुमार बरुआ और अमित कुमार सिंह समेत अन्य आरोपियों को भी जमानत मिलने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कई आरोपियों के नाम गिनाए। गौरव गोगोई ने कहा कि जिस उद्देश्य से पहले यह कानून लाया गया था, उसमें वह सफल नहीं हो सका और जिस मंशा के साथ अब संशोधन लाया जा रहा है, उसमें भी सफलता की संभावना नहीं दिखती। उन्होंने कहा यह कानून आपकी विफलता का स्मारक है।

बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्र होंगे रिहा

नईदिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह हुए विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने पर गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए उन सभी छात्रों को मंगलवार को रिहा करने का आदेश दिया जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार और असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा केरल सरकारों से जवाब मांगा है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रव्यापी छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस कर्मियों को आई चोटों के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच

जरूरी है। न्यायालय ने इस मामले में अंतरिम निर्देशों की एक श्रृंखला जारी करते हुए यह भी संकेत दिया कि वह अपने एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में

छात्रों और पुलिस कर्मियों को आई चोटों की जांच जरूरी

एक विशेष जांच दल का गठन कर सकती है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ पुलिस बर्बरता के आरोपों वाली याचिकाओं के साथ-साथ घायल पुलिस कर्मियों और मीडियाकर्मियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने छात्र प्रदर्शनकारियों की व्यक्तिगत जानकारी और डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने तथा ऐसी जानकारी को फिलहाल सार्वजनिक न करने का आदेश दिया। न्यायालय ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि प्रदर्शनकारियों के व्यक्तिगत विवरण प्रकाशित न किए जाएं। इसके साथ ही, बिना किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने को लेकर कोई भी दंडात्मक या दमनकारी कार्रवाई न की जाए। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को इन घटनाओं से जुड़े सभी सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज, कैमरा रिकॉर्डिंग, वायरलेस रिकॉर्ड और पीसीआर लॉग को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

रायपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित एकलव्य संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों से नीट-2026 में सफल विद्यार्थियों से आत्मीय चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी विद्यार्थियों को उनकी उल्लेखनीय सफलता पर बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़, विशेषकर जनजातीय समाज के लिए गर्व का विषय है।

प्रमुख समाचार

पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मांगी माफी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने का मामला अब गंभीर रूप ले चुका है। मेटा ने इस घटना पर सरकार से माफी मांगते हुए स्वीकार किया है कि वीडियो किसी नीति उल्लंघन की वजह से नहीं, बल्कि एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण गलती से हट गया था। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि जैसे ही गड़बड़ी का पता चला, वीडियो को दोबारा प्लेटफॉर्म पर बहाल कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार इस पूरे मामले को हल्के में नहीं ले रही है। संबंधित विभाग यह पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर किस वजह से प्रधानमंत्री के आधिकारिक वीडियो को हटाया गया और मेटा की ओर से दी गई तकनीकी खराबी की सफाई कितनी सही है। मेटा के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि संबंधित कंटेंट गलती से हट गया था और अब उसे पूरी तरह बहाल कर दिया गया है। कंपनी ने इस घटना के लिए खेद भी जताया है। जानकारी के अनुसार, मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर यह वीडियो भारत में कुछ समय के लिए दिखाई देना बंद हो गया था। बाद में प्रतिबंध हटने के बाद यह फिर से सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो गया।

धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। कांग्रेस की लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा के एक फैसले पर सवाल उठाया। दरअसल, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में उनका स्वागत किया गया। इस पर प्रियंका ने पूछा कि

सत्तारूढ़ गठबंधन ऐसे मंत्री का स्वागत कैसे कर सकता है? यहां पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने प्रधान के समर्थन में नारे लगाने । उनके इस्तीफे के बाद उनका स्वागत करने के लिए भाजपा और एनडीए सांसदों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि यह शर्मनाक है? उन परिस्थितियों पर विचार करें जिनके तहत उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर भी उनका यहां ऐसे स्वागत किया जा रहा है जैसे कोई सुपरस्टार आ रहा हो। उन्होंने आगे कहा कि इस सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज भी छात्रों को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा है कि कुछ इंस्टाग्राम हैंडल पर लड़कियों की तस्वीरें पोस्ट की गई हैं।

राजग की बैठक में शामिल हुए एनसीपीआई सांसद

नयी दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल हुए सांसदों के एक समूह ने पहली बार, मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया। 'मंगल मिलन' में

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शीर्ष केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे। तृणमूल कांग्रेस के 20 लोकसभा सदस्य हाल में अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करने के बाद एनसीपीआई में शामिल हुए थे। हालांकि, वे लोकसभा में तृणमूल सांसदों से अलग बैठ रहे हैं, लेकिन सदन के अध्यक्ष ओम बिरला ने एनसीपीआई को मान्यता देने पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। एनसीपीआई में शामिल होने के बाद, सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राजग के प्रति अपनी निष्ठा जताई। इस समूह के एक प्रमुख नेता, सुदीप बंद्योपाध्याय ने हाल में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी।राजग संसदीय दल की बैठक संसद भवन परिसर में हुई।

पेपर लीक मामला, भाजपा के नेता ही चला रहे हैं रैकेट : राउत

मुंबई। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने 28 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए एंटी-पेपर लीक बिल की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे बड़ा पेपर लीक रैकेट भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही चलता है और कहा कि सिर्फ़ कानून पास करने से यह समस्या हल नहीं

होगी। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए, राज्यसभा सांसद ने प्रस्तावित कानून को सख्त सज़ाओं वाला वही पुराना बिल बताया और कहा कि छात्रों के बड़े विरोध-प्रदर्शन पहले ही हो चुके हैं। संजय राउत ने कहा कि पेपर लीक के मुद्दे पर निश्चित रूप से चर्चा होगी, लेकिन पेपर लीक के खिलाफ़ दुनिया का सबसे बड़ा विरोध-प्रदर्शन भारत में जंतर-मंतर पर हुआ था। अब एक नया बिल पेश किया गया है। ऐसा लगता है कि मोदी जी को लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। राउत ने आगे कहा कि यह वही पुराना बिल है। बस इतना बदला है कि जेल की सज़ा एक साल से बढ़ाकर दस साल कर दी गई है। और जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है।

अनुच्छेद-370 की बहाली को लेकर पीडीपी पांच को करेगी प्रदर्शन

श्रीनगर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी)अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी अनुच्छेद 370 की बहाली और 'कश्मीर मुद्दे के समाधान' की मांग को लेकर पांच अगस्त को पूरे जम्मू-कश्मीर में जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह

घोषणा पीडीपी के 27वें स्थापना दिवस के मौके पर यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की। उन्होंने कहा, ''यहां मौजूद हमारे सभी लोग पांच अगस्त को अपने-अपने जिलों में अनुच्छेद 370 और 35ए को बहाल करने और कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करेंगे।'' महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर की गयी अपनी टिप्पणियों के लिए भी खेद जताया। केंद्र शासित प्रदेश में सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस के नेता और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तथा अन्य लोगों ने पीडीपी अध्यक्ष की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए उन पर कश्मीरी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग को सही ठहराने का आरोप लगाया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा, ''अगर कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा पर मेरे द्वारा की गई टिप्पणी से कोई आहत हुआ है।

नेता-विहीन जनाक्रोश, बदलते दौर की नई राजनीतिक तस्वीर

जयसिंह रावत

भारतीय राजनीति एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां सूचना महाक्रांति ने जनमत निर्माण और राजनीतिक भागीदारी के पारंपरिक स्वरूप को बदल दिया है। चुनावी सफलता, मजबूत संगठन और संसाधनों के बावजूद अब कोई भी राजनीतिक दल जनभावनाओं को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता।

हाल के स्वत:स्फूर्त युवा आंदोलनों ने स्पष्ट किया है कि बिना किसी स्थापित नेता, संगठन या दल के भी लाखों लोग किसी मुद्दे पर एकजुट हो सकते हैं। सोशल मीडिया ने हर नागरिक को जनमत का सक्रिय वाहक बना दिया है। यह बदलता परिदृश्य सभी राजनीतिक दलों के लिए संकेत है कि नई पीढ़ी की राजनीति संवाद, पारदर्शिता और त्वरित जनसंपर्क पर आधारित होगी।

ारत में आंदोलनों का समृद्ध इतिहास रहा है। स्वतंत्रता संग्राम, जेपी आंदोलन, मंडल आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और किसान आंदोलनों तक लगभग हर बड़े जनआंदोलन का एक स्पष्ट नेतृत्व और संगठन रहा। सरकारें भी ऐसे आंदोलनों से बातचीत प्रतिनिधियों के माध्यम से करती थीं। आज स्थिति बदल चुकी है।

डिजिटल तकनीक और इंटरनेट ने जनसंपर्क का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया है। अब किसी एक मुद्दे पर देशभर के लोग बिना किसी केंद्रीय नेतृत्व के एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं। ऐसे आंदोलनों को किसी राजनीतिक दल का आंदोलन कहकर खारिज करना या किसी एक नेता को निशाना बनाकर उनकी धार कम करना पहले जैसा आसान नहीं रह गया है। हाल के विरोध प्रदर्शनों को केवल किसी एक परीक्षा, भर्ती या प्रशासनिक निर्णय तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। इनके पीछे युवाओं की व्यापक चिंताएं दिखाई देती हैं। रोजगार के सीमित अवसर, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप, नियुक्तियों में विलंब, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना युवाओं में असंतोष पैदा कर रही है।

भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल है। यह युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन यदि उसकी आकांक्षाओं और उपलब्ध अवसरों के बीच दूरी बढ़ती है तो उसका असर राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता—तीनों पर पड़ना स्वाभाविक है। आज का युवा केवल भाषण नहीं,

बल्कि अवसर, पारदर्शिता और परिणाम चाहता है।भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत संगठन, बूथ स्तर तक सक्रिय कार्यकर्ता और प्रभावी चुनावी प्रबंधन माना जाता है। लेकिन जब विरोध किसी विपक्षी दल के बजाय स्वत:स्फूर्त सामाजिक असंतोष के रूप में सामने आए, तब चुनौती का स्वरूप बदल जाता है। ऐसे आंदोलनों में विरोध का कोई एक चेहरा नहीं होता। इसलिए उन्हें विपक्ष की साजिश बताकर पूरी तरह खारिज करना भी कठिन होता है। सरकार के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ जनता का विश्वास बनाए रखने की भी चुनौती रहती है। लोकतंत्र में जनविश्वास किसी भी सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी होता है।

इन आंदोलनों से विपक्ष को राजनीतिक अवसर अवश्य मिलता है, लेकिन वह स्वत: उनका स्वाभाविक नेतृत्व हासिल नहीं कर लेता। यदि विपक्ष इन आंदोलनों के साथ खड़ा दिखाई देता है तो उसे राजनीतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन यदि वह उन्हें पूरी तरह अपने राजनीतिक अभियान में बदलने का प्रयास करता है तो आंदोलन की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। यानी यह नया राजनीतिक परिदृश्य सत्ता और विपक्ष—दोनों से अधिक परिपक्व और संवेदनशील राजनीति की अपेक्षा करता है। इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक सूचना महाक्रांति है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल संचार ने सूचना के प्रवाह को पूरी तरह लोकतांत्रिक बना दिया है। कभी जनमत निर्माण का दायित्व मुख्यत: समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन जैसे मुख्यधारा के मीडिया पर निर्भर था, लेकिन अब सूचना का संसार पूरी तरह बदल चुका है।यह किसी से छिपा नहीं है कि समय-समय पर मुख्यधारा के मीडिया पर राजनीतिक, आर्थिक अथवा व्यावसायिक दबावों और प्रलोभनों के आरोप लगते रहे हैं। चाहे वे आरोप सही हों या गलत, लेकिन सूचना महाक्रांति ने अब ऐसा वैकल्पिक मंच उपलब्ध करा दिया है, जिसे पूरी तरह नियंत्रित करना लगभग असंभव है। आज लगभग हर स्मार्टफोन धारक एक संभावित %सिटिजन रिपोर्टर है।घटनास्थल पर मौजूद व्यक्ति कुछ ही क्षणों में फोटो, वीडियो और प्रत्यक्ष अनुभव दुनिया के सामने रख सकता है। यही कारण है कि किसी घटना को पूरी तरह दबा देना या केवल एक ही पक्ष की कहानी स्थापित करना पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन हो गया है। हालांकि, यह भी उतना ही सच है कि सोशल मीडिया अपुष्ट सूचनाओं, दुष्प्रचार और अफवाहों का माध्यम भी बन सकता है। इसलिए सूचना महाक्रांति के इस युग में नागरिकों, मीडिया संस्थानों और सरकार—तीनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि सूचना की सत्यता और विश्वसनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

कोयलीबेड़ा के जंगल में नक्सल डंप बरामद सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी

बीडीएस टीम ने सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर ही विस्फोटक सामग्री को डिफ्यूज कर नष्ट कर दिया

कांकेर- उत्तर बस्तर के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के जंगल से नक्सल डंप बरामद हुआ है। विस्फोटक को मौके पर बीडीएस टीम ने नष्ट कर दिया है।

गटटाकाल और दरवीकोड़ो के बीच जंगल-पहाड़ी इलाके में नक्सलियों का डंप मिला है। जवानों ने हथियार, गोला-बारूद, यूबीजीएल, बीजीएल सेल, डेटोनेटर और विस्फोटक सामग्री सहित बड़ी मात्रा में सामान बरामद किया।

दरअसल कांकेर पुलिस, डीआरजी, बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम कोयलीबेड़ा क्षेत्र में लगातार सघन सर्चिंग अभियान चला रही है। इसी अभियान के दौरान नक्सल डम्प मिला है। नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में जवानों के साथ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार डंप ढूंढने की कार्रवाई जारी है, सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सघन सर्चिंग अभियान किया जा रहा है। अब तक 40 से ज्यादा नक्सल डंप बरामद किया गया है ये नक्सल सामग्री मिली एक यूबीजीएल, एक देशी कट्टा, दो यूबीजीएल सेल, दो एके-47 राउंड, 14 राउंड ।303 रायफल, 99 एसएलआर राउंड, 21 आठ एमएम राउंड, 23 नौ एमएम पिस्टल राउंड, दो एके-47 मैगजीन, एक एसएलआर मैगजीन, 10 बीजीएल सेल, 10 बीजीएल राउंड, 20 डेटोनेटर, 10 किलोग्राम विस्फोटक बारूद, एक दूरबीन सहित अन्य नक्सली सामग्री बरामद कांकेर पुलिस ने बताया कि मौके पर मिले बीजीएल सेल, डेटोनेटर और विस्फोटक बारूद को बीडीएस टीम ने सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर नष्ट कर दिया। पुलिस का कहना है कि नक्सल प्रभावित सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त सर्चिंग अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

झोपड़ी में पढ़ रहे नौनिहाल, राशि आने के बाद भी नही सुधरी हालत

बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुआ था स्कूल

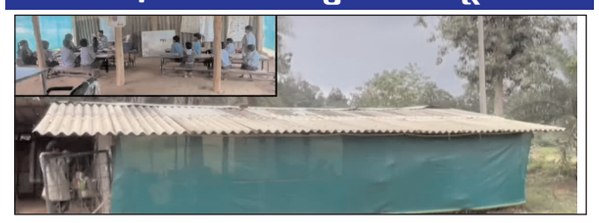

दंतेवाड़ा। बस्तर की बदलती तस्वीर, विकास और शिक्षा के बड़े-बड़े दावों के बीच दंतेवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव की हकीकत आज भी सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है। ग्राम पंचायत हितामेटा के आश्रित गांव झिटकीपारा में प्राथमिक शाला के बच्चे पिछले करीब एक साल से झोपड़ीनुमा अस्थायी कक्ष में पढ़ाई करने को मजबूर हैं।

26 अगस्त 2025 को आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने स्कूल भवन को इस कदर क्षतिग्रस्त कर दिया कि वह बच्चों के बैठने लायक नहीं बचा। विडंबना ये है कि आपदा को एक वर्ष पूरा होने वाला है, लेकिन आज तक नया भवन नहीं बन पाया है। 26 अगस्त 2025 को दक्षिण बस्तर सहित पूरे बस्तर संभाग में आई बाढ़ और प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई थी।

दंतेवाड़ा जिले में भी कई गांवों की सड़कें, पुल-पुलिया, शासकीय भवन और स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए थे। झिटकीपारा का प्राथमिक विद्यालय भी इस आपदा की चपेट में आ गया। बाढ़ का पानी स्कूल भवन में भर गया, जिससे दीवारों में गहरी दरारें पड़ गईं और छत पूरी तरह कमजोर हो गई।

आज भी बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है और भवन कभी भी गिर सकता है।बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यालय भवन में पढ़ाई बंद कराकर अस्थायी व्यवस्था की। स्कूल परिसर के बाहर बांस, फेंसिंग और टीन की छत से एक झोपड़ीनुमा कक्ष तैयार किया गया, जहां पहली से पांचवीं तक के सभी छात्र-छात्राओं को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। सीमित जगह, बरसात के दौरान टपकती छत, गर्मी में उमस और अन्य असुविधाओं के बीच नन्हे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।अस्थायी व्यवस्था लंबे समय तक समाधान नहीं हो सकती।छोटे-छोटे बच्चे एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं, जिससे पढ़ाई भी प्रभावित होती है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती हैवहीं अभिभावकों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है।झिटकीपारा के ग्रामीण और अभिभावक चाहते हैं कि निर्माण कार्य में अब और देरी न हो। सिर्फ स्कूल ही नहीं, बल्कि कई ग्रामीण सड़कों और पुल-पुलियों की स्थिति भी अब तक पूरी तरह नहीं सुधर सकी है।इससे ग्रामीणों को रोजमर्रा की आवाजाही में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।ऐसे में विकास और बुनियादी सुविधाओं के दावों के बीच झिटकीपारा का यह स्कूल व्यवस्था की धीमी रफ्तार की तस्वीर पेश करता है।गौरतलब है कि बाढ़ के बाद स्वयं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दंतेवाड़ा पहुंचकर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था।

उन्होंने आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद दंतेवाड़ा जिले के लिए 53 करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की थी, ताकि क्षतिग्रस्त सड़कें, पुल-पुलिया, शासकीय भवन और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कराया जा सके। इसके बावजूद झिटकीपारा जैसे कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं।एक वर्ष पहले आई प्राकृतिक आपदा के निशान आज भी झिटकीपारा के इस विद्यालय में साफ दिखाई देते हैं।सवाल यह है कि क्या अगली बारिश से पहले इन मासूम बच्चों को नया और सुरक्षित स्कूल मिल पाएगा।

कोरबा में नेताजी को जान से मारने की धमकी, दर्ज कराई शिकायत

कोरबा। यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अदनान मेमन को जान से मारने की धमकी मिली है। अदनान मेमन ने इस बात की शिकायत पुलिस से की है। सोशल मीडिया के जिस अकाउंट से ये धमकी मिली है, उस प्रोफाइल की डिटेल्स भी पुलिस को उपलब्ध कराई गई है। युवा कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस से धमकी देने वाले पर ठोस कार्रवाई की मांग की गई है।पुरानी बस्ती कोरबा में रहने वाले अदनान मेमन ने पुलिस से जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत की है। अदनान यूथ कांग्रेस के शहर ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। अदनान का कहना है कि मेरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पोस्ट में एक कथित व्यक्ति जिसका नाम सोनम चंद्रवंशी है, द्वारा मुझे गोली मारने जैसी धमकी दी गई है। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव और सदस्यता अभियान का आधिकारिक ऐलान राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन में किया गया था। ?इन चुनावों में 18 से 35 वर्ष तक के युवा भाग ले रहे हैं। नियमों के अनुसार एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पद रहेगा। चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने पर उम्मीदवारी तुरंत रद्द किए जाने का प्रावधान है। साथ ही एससी, एसटी, महिलाओं और बीपीएल वर्ग के लिए विशेष छूट व प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के तहत ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला स्तर और प्रदेश अध्यक्ष तक के पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। वर्तमान में विभिन्न पदों के लिए दावेदारी पेश करने वाले युवा नेता सक्रिय रूप से सदस्यता बढ़ाने, कार्यकर्ताओं का समर्थन जुटाने और अपना जनाधार मजबूत करने में लगे हुए हैं

2.45 लाख महिलाएं करेंगी पौधारोपण

सेल्फी अपलोड करने पर मिलेगा ऑनलाइन सर्टिफिकेट

बालोद। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य पहली बार 30 जुलाई को 'महतारी वंदन वृक्षारोपण अभियान' आयोजित किया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए बालोद जिले में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशन में सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं और अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने के प्रयास में जुटे हैं।

जिले में महतारी वंदन योजना की 2 लाख 45 हजार से अधिक लाभान्वित महिलाओं के साथ-साथ अन्य महिलाओं की भी व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि प्रत्येक महिला अपने घर, आंगन या उपयुक्त सार्वजनिक स्थल पर पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम का हिस्सा बने। विशेष बात यह है कि महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों में पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। अभियान में करीब सवा दो लाख पौधे वन विभाग की नर्सरियों से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया कि बालोद जिले में 2 लाख 45 हजार से अधिक पौधे रोपे जाएंगे, जिसको लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि बालोद के पर्यावरण पार्क को पौधे रोपण के लिए चुना गया है।

जनप्रतिनिधियों द्वारा भी आम नागरिक से अपील की जा रही है ताकि इस मुहिम को सफल बनाया जाए। इसके अलावा आधिकारिक वेबसाइट mybalod.com पर नागरिक पौधे के साथ ली गई अपनी फोटो या सेल्फी अपलोड कर सकेंगे और ऑनलाइन प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) भी डाउनलोड कर सकेंगे।

कलेक्टर ने बताया कि अब तक 2 लाख से अधिक गड्ढे खोदे जा चुके हैं और पौधों की आपूर्ति भी संबंधित स्थानों तक पहुंचा दी गई है।

बस्तर के जंगलों पर हाई टेक पहरा

शिकारियों और लकड़ी तस्करों पर वन विभाग की नजर

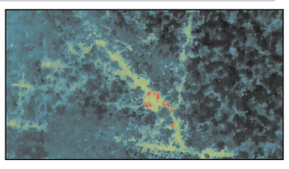

जगदलपुर। बस्तर में जंगलों की सुरक्षा अब हाई-टेक तकनीक से की जा रही है। वन विभाग ने जंगलों में अवैध कटाई, शिकार और वन्यजीवों की निगरानी के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल शुरू किया है।

यह तकनीक रात के अंधेरे और घने जंगलों में भी इंसानों और वन्यजीवों की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम है। फिलहाल बस्तर वन मंडल, कांकेर वन मंडल के सहयोग से ड्रोन की मदद ले रहा है। जल्द ही बस्तर को अपना थर्मल ड्रोन भी मिलने वाला है। जगदलपुर योगेश रात्रे ने बताया कि इस आधुनिक तकनीक के जरिए जंगलों की चौबीसों घंटे निगरानी कर रहा है। थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरे शरीर की गर्मी को पहचानकर रात के समय भी वन्यजीवों और संदिग्ध गतिविधियों की स्पष्ट तस्वीर उपलब्ध कराते हैं। इससे भालू, तेंदुए, हाथियों, हिरण समेत अन्य वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो गया है। यह तकनीक मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में भी मददगार साबित होगी। यदि हाथियों या अन्य जंगली जानवरों की आवाजाही ग्रामीण इलाकों की ओर होती है तो थर्मल ड्रोन के जरिए समय रहते उनकी लोकेशन का पता लगाकर ग्रामीणों को अलर्ट किया जा सकेगा। एसडीओ ने बताया कि इस तकनीक से जन-धन के नुकसान की आशंका भी कम होगी। रात के समय होने वाली अवैध लकड़ी कटाई, तस्करी और वन्यजीवों के शिकार जैसी गतिविधियों पर भी अब वन विभाग की नजर रहेगी। ड्रोन से मिलने वाले फुटेज के आधार पर क्विक रिस्पांस टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी। जिससे जंगलों में होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। स्क्वह ने बताया कि ड्रोन की एक प्रकिया में 09 हिरणों का झुंड एक साथ दिखाई दिया है। आगे ऐसी ही जानकारियां जुटाई जाएगी।

बड़े बेन्दरी में 36.01 लाख के स्वास्थ्य व सांस्कृतिक भवन का भूमिपूजन-लोकार्पण

कोण्डागांव। विकासखंड कोण्डागांव के ग्राम पंचायत बड़े बेन्दरी में सोमवार को 36.01 लाख रुपये की लागत के दो महत्वपूर्ण विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया गया। बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोण्डागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी ने 28.51 लाख रुपये की लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमिपूजन तथा 7.50 लाख रुपये की लागत से निर्मित सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक सुश्री लता उसेंडी ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल सहित मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण से बड़े बेन्दरी सहित आसपास के ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं, सांस्कृतिक भवन के निर्माण से ग्रामीणों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक गतिविधियों के लिए एक उपयुक्त स्थान मिल सकेगा।उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन निर्माण कार्यों से ग्रामीणों को सुविधाएं मिलने के साथ ही क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में बड़े बेन्दरी सहित आसपास के क्षेत्रों में भी आवश्यकतानुसार विकास कार्यों का विस्तार किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बस्तर में सिंचाई का दावा फेल, कई साल से अधूरी है योजना

बस्तर। बस्तर में सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेतों तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के बड़े-बड़े दावे करती है। लेकिन बस्तर के ही एक गांव में सरकारी लापरवाही के कारण पिछले चार साल से सिंचाई योजना पूरी नहीं हो सकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि लाखों रुपये खर्च कर पाइपलाइन बिछा दी गई। लेकिन ट्रांसफार्मर और बिजली कनेक्शन अब तक नहीं लगा है।ट्रांसफार्मर और बिजली लाइन ना होने के कारण ये पाइपलाइन ग्रामीणों के किसी काम नहीं आ रही है। इतने साल तक बिजली को लेकर कोई प्रबंध नहीं होने के कारण पाइपलाइन भी खराब होने लगी है। वहीं दूसरी ओर किसान सिंचाई के अभाव में खेती नहीं कर पा रहे हैं।वहीं मानसून की बेरुखी से भी किसान परेशान हैं। सरपंच मधुसूदन बघेल का कहना है कि ग्राम पंचायत उसरीबेड़ा में वर्ष 2022-23 में उद्यान सिंचाई योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ था। योजना का उद्देश्य इंद्रावती नदी के पानी से किसानों के खेतों तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना था। लेकिन चार साल बीत जाने के बाद भी योजना अधूरी है।

बारिश बनी अभिशाप: जलभराव से 100 एकड़ फसल बर्बाद

धमतरी। धमतरी में इंद्रदेव की मेहरबानी अबकी बार किसानों के लिए अभिशाप बनती दिख रही है। रुक-रुक कर हो रही बारिश ने अन्नदाताओं के चेहरों पर असमंजस की लकीर खींच दी है। एक तरफ फसल की प्यास बुझने की खुशी है तो दूसरी तरफ खेतों में जलभराव से फसल बर्बादी का गम है। धमतरी जिले के करेली बड़ी में भारी बारिश ने किसानों की नींद उड़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि खेत अब तालाब में तब्दील हो चुके हैं और करीब सौ एकड़ लहलहाती फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। निस्तारी का नाला था जो माटी से पट गया है। बेबस किसान का हर एक अरमान पानी में कट गया हैकिसानों का कहना है कि गांव में पानी की निकासी के लिए बना नाला पूरी तरह से पट चुका है, जिसके चलते बारिश का पानी रास्तों से निकलकर सीधे खेतों में भर गया है। नतीजा यह है कि लगभग सौ एकड़ की फसल पानी में डूबकर नष्ट हो गई है। अपनी इस गाढ़ी कमाई को डूबता देख आज बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से पानी की सही निकासी निस्तारी की गुहार लगाई।

दशहत फैलाने चिपकाए फर्जी नक्सली बैनर-पोस्टर 2 गिरफ्तार

कांकेर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पिपली बुर्गी क्षेत्र में नक्सली बैनर-पोस्टर फर्जी निकले। पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए भाजपा नेता शिवा अनिल मिस्त्री और सहयोगी रोहित मल्लिक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक, शिवा मिस्त्री कोयलीबेड़ा जनपद पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 24 इरपानार से निर्वाचित सदस्य है। शिवा महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे क्षेत्र में खनन कंपनी के लिए पोकलेन मशीन और परिवहन का काम करता था। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को पिपली बुर्गी से 5 किसी दूर पर साइनबोर्ड के नीचे संदिग्ध लाल कपड़े का बैनर मिला, जिसमें नक्सली संगठन होने का दावा करते हुए धमकी दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी एम। रमेश ने आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। थाना में संबंधित धाराओं में मामल दर्ज कर जांच शुरू की गई। मुखबिर से मिली जानकारी के आद गढ़चिरौली निवासी 48 वर्षीय शिवा मिस्त्री और पखांजूर निवासी 25 वर्षीय रोहित रंजित मल्लिक को गिरफ्तार किया गया।

आजादी के 79 वर्षों बाद भिरागांव को मिली पक्की सड़क की सौगात

कोण्डागांव। विकासखंड माकड़ी अंतर्गत ग्राम पंचायत भिरागांव के ग्रामीणों का वर्षों पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है। आजादी के 79 वर्षों बाद ग्राम पंचायत भिरागांव से सड़क पारा बरकई तक 5 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन संपन्न हुआ। लगभग 703.07 लाख रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क कग्रामीणों की बहुप्रतिक्षित मांग थी। भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोण्डागांव विधायक सुश्री लता उसेण्डी उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, पेयजल एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सड़क निर्माण से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान बनेगी तथा ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से जर्जर सड़क के कारण विशेषकर बरसात के मौसम में आवागमन अत्यंत कठिन हो जाता था।

लगातार बारिश से सैकड़ों एकड़ धान के खेत जलमग्न

बिलासपुर। जिले में लगातार हुई मूसलाधार बारिश का सबसे बड़ा असर अब खेती-किसानी पर दिखाई देने लगा है। शहर से लगे कोनी और सेंदरी क्षेत्र के सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न हो गए हैं। धान की रोपाई के बाद खेतों में लबालब पानी भर जाने से फसल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है। किसान इसके लिए प्राकृतिक जल निकासी मार्गों पर हुए अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियों के निर्माण को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि जल निकासी के प्राकृतिक नालों पर अतिक्रमण कर रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिससे बारिश का पानी खेतों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसके चलते कोनी और सेंदरी के सैकड़ों एकड़ खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं। धान की रोपाई के बाद लगातार भरे पानी ने फसल को पूरी तरह डुबो दिया है और खेतों में जल निकासी पूरी तरह ठप है। किसान दिन-रात खेतों की निगरानी कर रहे हैं लेकिन पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं है। उनका कहना है कि यदि दो-तीन दिन और यही स्थिति बनी रही तो पूरी फसल सड़ जाएगी।

सरस्वती साइकिल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप

रवि भगत ने स्कूल में मचाया हंगामा, पुलिस हिरासत में भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष

रायगढ़/लैलूंगा। रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुपाकानी गांव में सरस्वती साइकिल वितरण योजना के दौरान जमकर हंगामा हुआ। भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने साइकिलों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सरकारी योजना में घटिया साइकिल वितरण किए जाने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को भी घेरा और योजना में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।

बताया जा रहा है कि स्कूल परिसर में छात्राओं को सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिलें दी जा रही थीं। इसी दौरान रवि भगत मौके पर पहुंचे और साइकिलों की गुणवत्ता को लेकर आपत्ति जताई। आरोप है कि उन्होंने साइकिल लेने पहुंची छात्राओं से साइकिलें वापस करवाने को कहा, जिसके बाद मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। रवि भगत ने आरोप लगाया कि छात्राओं को वितरित की जा रही साइकिलें गुणवत्ता के मानकों पर खरी नहीं उतरतीं। सरकारी योजना के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही।

वहीं, स्कूल परिसर में हुए हंगामे और रवि भगत के रवैये को लेकर पुलिस में शिकायत किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। मामले की सूचना मिलते ही लैलूंगा थाना पुलिस मौके पहुंची और उन्हें हिरासत में लिया।

इसकी पुष्टि एसएसपी शशिमोहन सिंह ने की है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सरस्वती साइकिल वितरण योजना को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

सोलर बैटरी खराब होने से 23 छात्र परेशान

एमसीबी। विकासखंड भरतपुर के बालक छात्रावास, बड़गांवकल में 23 छात्र हैं। यह छात्रावास घने जंगल और पेड़-पौधों से घिरे क्षेत्र में स्थित है। विकासखंड मुख्यालय से इसकी दूरी करीब 55-60 किलोमीटर है। इस छात्रावास में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में छात्र परेशान हैं। सबसे बड़ी समस्या बिजली व्यवस्था की है। छात्रों ने बताया कि सोलर सिस्टम की बैटरी लंबे समय से खराब है। स्कूल खुलने के बाद से ही बिजली की सुविधा नहीं मिल रही है। कक्षाओं में पर्याप्त रोशनी नहीं मिलती, जिससे पढ़ाई में कठिनाई होती है। स्कूल परिसर में आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंधेरा रहने के कारण रात में बाहर आने-जाने में भी डर लगता है। जंगल क्षेत्र होने से सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीवों का खतरा हमेशा बना रहता है।

स्थानीय लोगों और छात्रों ने संबंधित विभाग से छात्रावास की सोलर बैटरी को जल्द ठीक कराने के साथ ही नियमित बिजली व्यवस्था की मांग की है। वहीं बालक छात्रावास बड़गांवकल के अधीक्षक अमरजीत ने बताया कि सोलर सिस्टम की खराब बैटरी और बिजली समस्या को लेकर संबंधित विभाग को कई बार मौखिक और लिखित शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं किया गया है।

अधीक्षक ने कहा कि अधिकारी और संबंधित कर्मचारी हर बार आश्वासन देते हैं, लेकिन मरम्मत के लिए कोई नहीं पहुंचता। लंबे समय से सोलर सिस्टम खराब पड़ा है, जिससे छात्रावास में रह रहे 23 विद्यार्थियों को पढ़ाई और दैनिक गतिविधियों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विभाग से जल्द से जल्द सोलर सिस्टम की मरम्मत कराने की मांग की है।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भोरमदेव धाम में की पूजा-अर्चना

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

मंगलवार को सपत्नीक श्रीमती कौशल्या साय के साथ विश्वप्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की तथा मंदिर की परिक्रमा कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और जनकल्याण की मंगलकामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पंच दिवसीय महा चतुर शुद्धि सहस्त्र कलशम् महाअनुष्ठान में भी सम्मिलित हुए और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता कर प्रदेश की उन्नति, सामाजिक सद्भाव और लोकमंगल की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भोरमदेव छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सनातन परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का गौरवशाली प्रतीक है। ऐसे महाअनुष्ठान हमारी प्राचीन वैदिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के साथ-साथ समाज में सकारात्मक ऊर्जा, सद्भाव और लोककल्याण की भावना को भी सशक्त बनाते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आगामी 30 जुलाई से भगवान शिव की आराधना का पावन श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है। पिछले दो वर्षों से उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के साथ भोरमदेव धाम पहुंचने वाले कांवड़ यात्रियों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा भारतीय संस्कृति की जीवंत परंपरा का प्रतीक भी है।

भारतीय सेना में जल्द स्थापित हो सकती है बस्तर रेजिमेंट! रक्षामंत्री का आया जवाब

रायपुर। भारतीय सेना में जल्द ही बस्तर रेजिमेंट स्थापित हो सकती है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा था, जिसका जवाब आ गया है। राजनाथ सिंह ने लिखा कि विजय शर्मा का पत्र प्राप्त हुआ, जो भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट की स्थापना किए जाने के संबंध में है। उपर्युक्त मामले की जांच करवाई जा रही है। बता दें विजय शर्मा ने 26 जून को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा था कि छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी बाहुल्य बस्तर संभाग के जवान विगत वर्षों में नक्सल विरोधी अभियानों में अपनी वीरता एवं अदम्य साहस का परिचय दे चुके हैं। ये दुर्गम क्षेत्रों की विषम परिस्थितियों में भी गुरिल्ला युद्ध में अभ्यस्त हैं। भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट का गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय विकास और सामाजिक स्थिरता में योगदान देने वाली एक रणनीतिक पहल होगी। यह बस्तर के युवाओं को राष्ट्र की सेवा करने के लिए एक सुनियोजित मार्ग प्रदान करेगी। साथ ही क्षेत्र में गौरव, अनुशासन और आर्थिक प्रगति को भी बढ़ावा देगी। अत: भारतीय सेना में 'बस्तर रेजिमेंट की स्थापना किये जाने का सादर अनुरोध है। इधर सीएम विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मांग की थी मंत्री जी का जवाब भी आ गया। अच्छा रहेगा.. स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी।

मेकाहारा के इमरजेंसी वार्ड में लगी आग, बन गया अफरा-तफरी का माहौल

रायपुर। राजधानी रायपुर के सबसे बड़े

शासकीय डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल (मेकाहारा) के इमरजेंसी वार्ड में मंगलवार की दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने से अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों, स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ से वार्ड में भर्ती मरीजों और उनके रिश्तेदारों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाडिय़ां मौके पर पहुंची। फिलहाल, दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। अग्निशमन अधिकारी पुष्पराज सिंह ने बताया कि आग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। एसी फटने की आशंका है। बिजली सप्लाई बंद कर मुआयना किया जाएगा, तभी वजह स्पष्ट हो पाएगी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को दी बधाई

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। राजनांदगांव की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 53 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ज्ञानेश्वरी को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीत कर भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी का नाम रोशन किया है। उनकी शानदार सफलता से राज्य के खिलाड़ी प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे।

समर्थ और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए अहम उपक्रम साबित होगा खेल : साव

उप मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ, राज्य में खेलों और खिलाड़ियों के लिए बेहतर इको-सिस्टम तैयार करने कर रहे मंथन

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहे स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित कॉन्क्लेव में देशभर के खेल प्रशासक, विशेषज्ञ, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, नामचीन खिलाड़ी और खेल संघों के पदाधिकारी भागीदारी कर रहे हैं। वे दिनभर अलग-अलग कई सत्रों में राज्य में खेल और खिलाड़ियों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने, खेल प्रतिभाएं को तराशने, उन्हें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए तैयार करने तथा खेल अधोसंरचना को मजबूत करने रोडमैप पर मंथन करेंगे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के पहले सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि समर्थ और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए खेल एक अहम उपक्रम साबित होगा। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के विकास से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के ज्यादा मौके मिलेंगे, उनका सर्वांगीण विकास होगा और वे एक मजबूत मानव संसाधन के रूप में तैयार होंगे, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए राज्य शासन हर तरह से तैयार है। इसके लिए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संघों को हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने राज्य की मौजूदा खेल अधोसंरचनाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करते हुए इनके संचालन और खिलाड़ियों के लिए उपलब्धता की सुदृढ़ व्यवस्था बनाने पर जोर दिया।

साव ने विजन टू विक्ट्री थीम पर आयोजित कॉन्क्लेव में नेतृत्व, खेल प्रोत्साहन और प्रतिभा खोज सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों के बीच होने वाली चर्चा के निष्कर्षों को राज्य में बेहतर खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए लागू किया जाएगा। उन्होंने सभी जिलों में खेल संघों के गठन, उनके व्यवस्थित व मजबूत ढांचे, नियमित गतिविधियों और पारदर्शी कार्यप्रणाली पर जोर दिया।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि आज यहां होने वाली चर्चा के निष्कर्षों को राज्य की नई खेल नीति में शामिल किया जाएगा। उन्होंने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने राज्य शासन द्वारा किए जा रहे आयोजनों और कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अभी 150 करोड़ रुपए से अधिक के खेल अधोसंरचनाओं के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। कॉन्क्लेव के पहले सत्र में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम की कप्तान सुश्री किरण पिस्दा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स खिलाड़ियों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है। राज्य में पहली बार हो रहे इस स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव से खिलाड़ियों को बहुत फायदा होगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने यहां रोडमैप तैयार होगा, जिसका लाभ सभी खिलाड़ियों को मिलेगा।

कॉन्क्लेव में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती तनुजा सलाम, पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर श्री राजेश चौहान, ओलंपियन श्री जिन्शन जॉनसन और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव श्री विक्रम सिसोदिया सहित अनेक स्पोर्ट्स प्रोफेशनल, सभी जिलों के खेल अधिकारी, प्रशिक्षक, पदक विजेता खिलाड़ी और खेल संघों के पदाधिकारी मौजूद थे।

सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर दें जोर : केदार कश्यप

■ अपैक्स बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों के साथ मंत्री ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को नई गति देने और बैंकिंग सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। नवा रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में आयोजित इस बैठक में छत्तीसगढ़ अपैक्स बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष व वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए।

प्रदेश के किसानों को बेहतर, पारदर्शी और आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री श्री कश्यप ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पूरी पारदर्शिता और समय पर पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए। सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के साथ-साथ डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर

विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। सहकारी संस्थाओं को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जनोन्मुखी बनाने के संबंध में विभिन्न सुझावों पर चर्चा की गई।

सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत है। सहकारिता व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए इसे मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सभी बैंकों के अध्यक्षों, पदाधिकारियों एवं अधिकारियों से आपस में बेहतर समन्वय बनाकर काम करने का आह्वान किया, ताकि प्रदेश का सहकारिता क्षेत्र अधिक सशक्त और जनहितैषी बन सके।

महिलाओं को सम्मान नहीं बिजली बिल का बोझ दे रही सरकार : उपाध्याय

कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर को 'महतारी वंदन वसूली योजना' का दिया नाम

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में स्मार्ट मीटर को बदलने कांग्रेस का अभियान जारी है। आज कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर को ''महतारी वंदन वसूली योजना'' का नाम दिया। इस दौरान पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा है कि हर इंसान का एक मासिक बजट होता है। 10 हजार-15 हजार महीना कमाने वाले व्यक्ति इस पैसे से घर का राशन भरते हैं, मकान का किराया देते हैं, बच्चों की स्कूली फीस पटाते हैं, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल डलाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर 1000-1500 आने वाला बिजली बिल अगर 5 से 7 गुना बढ़कर आ रहा है तो पूरे परिवार का बजट उथल-पुथल हो जाता है और जो परिवार चलाने वाला पालक है उसे बाजार से कर्ज लेना पड़ रहा है, जिससे व्यक्तियों को मानसिक परेशानी से जुझना पड़ रहा है।

विकास उपाध्याय ने कहा, महतारी वंदन योजना के नाम पर महिला बहनों को 1000 रुपये देकर उसकी वसूली बिजली बिल के माध्यम से कई गुना बीजेपी सरकार कर रही है। आज कांग्रेसजन एवं आमजनों ने मिलकर ''महतारी वंदन योजना के नाम से स्मार्ट मीटर'' का नामकरण किया और यह निरंतर जारी रहेगा।

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी दीपक बैज के नेतृत्व में पहले से ही महंगी बिजली दर को लेकर संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर को बदलने के लिए आवाज उठाई जा रही है। लोगों की सहमति से स्मार्ट मीटर निकालने के लिये फॉर्म भी भरवाये जा रहे हैं।

उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली होने के बाद भी छत्तीसगढ़ की जनता को महंगी बिजली बिल का झटका दिया जा रहा है। स्मार्ट मीटर के नाम पर सीधे जनता को लूटा जा रहा है और अडानी को लाभ पहुंचाते हुए बीजेपी अपना कमिशन निकाल रही है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल को महंगी करके जनता से जो पैसे वसूलने का काम बीजेपी सरकार कर रही है उन पैसों का उपयोग भारत देश के अन्य प्रदेशों में सांसद विधायकों को खरीदने में लगा रही है। विपक्षी पार्टीयों को तोड़ने में इस्तेमाल कर रही है और भाजपा अपने बड़े-बड़े कार्यालय खोलने एवं उनके साज-सज्जा में लगा रही है। एक तरफ जहां पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है वहीं बिजली की दर को बढ़ाकर भाजपा दोहरा मार प्रदेश की जनता को दे रही है।

विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगाये गये स्मार्ट मीटर के कारण काफी ज्यादा समस्या आ रही है। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ता पहले से ही बिजली की महंगी दर, स्मार्ट मीटर के कारण अनाप शनाप बिजली बिल, लो वोल्टेज, अघोषित बिजली कटौती से हलाकान है। पहले बिजली बिल हाफ योजना के तहत 400 यूनिट तक मिलने वाली छूट को खत्म किया गया और अब इस महंगाई में उपभोक्ता कई गुना ज्यादा बिजली बिल का भुगतान कहां से करेगी।

उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरप्लस बिजली का राज्य था, इस राज्य में आज निवासरत् जनता को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जबकि पिछली कांग्रेस की सरकार में बिजली बिल हॉफ योजना के माध्यम से कांग्रेस शासन के पाँच वर्षों में प्रत्येक घरों में लाखों रुपये की बचत हुई है।

रजत पदक जीतकर ज्ञानेश्वरी यादव ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का गौरव : मंत्री अग्रवाल

■ महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं

रायपुर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतने पर छत्तीसगढ़ की प्रतिभाशाली वेटलिफ्टर सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। श्री अग्रवाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव की यह उपलब्धि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व, सम्मान और प्रेरणा का विषय है। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्नैच में 88 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम तथा कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया है। यह उपलब्धि उनकी कठोर मेहनत, अनुशासन, समर्पण और अदम्य आत्मविश्वास का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर ज्ञानेश्वरी यादव के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि दृढ़ संकल्प, निरंतर अभ्यास और अथक परिश्रम से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। श्री अग्रवाल ने कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव की सफलता प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी प्रतिभा और

परिश्रम के बल पर विश्वस्तरीय मंच पर सफलता अर्जित कर यह सिद्ध किया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां किसी भी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकती हैं।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ज्ञानेश्वरी यादव भविष्य में भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारत और छत्तीसगढ़ के लिए स्वर्णिम उपलब्धियां अर्जित करेंगी। उन्होंने उनके उत्तम स्वास्थ्य, उज्ज्वल भविष्य और निरंतर सफलता की कामना करते हुए कहा कि प्रदेशवासियों को उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाएं लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर रही हैं। खिलाड़ियों की उपलब्धियां प्रदेश के युवाओं में खेलों के प्रति नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करती हैं तथा खेल संस्कृति को और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव का यह रजत पदक आने वाले समय में प्रदेश के अनेक युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का आधार बनेगा और उन्हें देश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

रायपुर रेल मंडल के स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा हेतु प्लेटफॉर्म शेल्टरों की सुविधा में वृद्धि

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का रायपुर रेल मंडल यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए आधारभूत यात्री सुविधाओं का निरंतर विस्तार कर रहा है। इसी क्रम में मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को धूप, वर्षा एवं अन्य प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म शेल्टरों का निर्माण एवं विस्तार लगातार किया जा रहा है।

प्लेटफॉर्म शेल्टर यात्रियों को ट्रेन की प्रतीक्षा के दौरान सुरक्षित एवं आरामदायक वातावरण उपलब्ध कराते हैं। इन शेल्टरों के निर्माण से प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षारत यात्रियों को प्रतिकूल मौसम से भी राहत मिलेगी तथा उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक एवं सुखद बनेगी ।रायपुर रेल मंडल में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत अब तक 89 नए प्लेटफॉर्म शेल्टरों का निर्माण किया गया है। इनमें भिलाई नगर स्टेशन पर 11, भिलाई पावर हाउस स्टेशन पर 17, सरोना स्टेशन पर 7, निपनिया स्टेशन पर 6, हथबंद स्टेशन पर 6, बिल्हा स्टेशन पर 4, मरौदा स्टेशन पर 2, मंदिर हसौद स्टेशन पर 12, बालोद स्टेशन पर

4, दल्लीराजहरा स्टेशन पर 4, भाटापारा स्टेशन पर 8 तथा तिल्दा-नेवरा स्टेशन पर 8 नए प्लेटफॉर्म शेल्टर निर्मित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, रायपुर रेल मंडल के उन स्टेशनों पर भी, जो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म शेल्टरों का निर्माण लगातार कराया जा रहा है। इस क्रम में देवबलोदा-चरौदा स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म शेल्टरों का निर्माण किया गया है। वहीं भैंसबोड़ स्टेशन पर 1, सलाईटोला स्टेशन पर 2, रिसामा स्टेशन पर 2, गुंडरदेही स्टेशन पर 2, लाटाबोर स्टेशन पर 2, लखौली स्टेशन पर 1 तथा राजिम स्टेशन पर 1 नए प्लेटफॉर्म शेल्टर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। रायपुर रेल मंडल द्वारा यात्री सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत आवश्यकता एवं यात्री आवागमन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म शेल्टरों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। विशेष रूप से उन स्टेशनों पर यह कार्य तेजी से किया जा रहा है जहाँ यात्री संख्या अधिक है तथा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास कार्य प्रगति पर हैं।

रायपुर रेल मंडल यात्रियों की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यात्री सुविधाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए निरंतर कार्यरत है। भविष्य में भी यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न विकासात्मक एवं जनहितकारी परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित किया जाता रहेगा। ताकि यात्रियों की यात्रा मंगलमय हो।

मुनगा बनेगा सुपोषित छत्तीसगढ़ का आधार : राजवाड़े

■ घर-घर मुनगा, हर आंगन मुनगा अभियान

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े ने प्रदेशवासियों से वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक मुनगा (सहजन) पौधे लगाने की अपील की है, ताकि कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण हो सके। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों और घरों में सुपोषण वृक्ष-मुनगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बच्चों, किशोरियों और माताओं को स्थानीय पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि मुनगा, जिसे मदर्स ट्री कहा जाता है, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन से भरपूर है और यह बच्चों के विकास, मातृ स्वास्थ्य तथा एनीमिया रोकथाम में अत्यंत उपयोगी है। सरकार पोषण सुधार को जनभागीदारी आधारित अभियान बना रही है। आंगनबाड़ी और घरों में मुनगा

पौधरोपण से पोषण जागरूकता और दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

मंत्री ने सांसदों, विधायकों, पंचायत प्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों में मुनगा पौधरोपण का नेतृत्व करने का आग्रह किया। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक पौधरोपण कर सुपोषण वाटिका विकसित करने पर जोर दिया।

उन्होंने महिला समूहों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों, युवाओं और संगठनों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। खेतों, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए मुनगा पौधे पोषण, पर्यावरण और हरियाली तीनों को बढ़ावा देंगे। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुनगा का हर पौधा स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने आह्वान किया कि घर-घर मुनगा, हर आंगन मुनगा—सुपोषित बचपन और स्वस्थ परिवार ही नए छत्तीसगढ़ की नींव है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह अभियान जनसहयोग से एक सशक्त जन-आंदोलन बनेगा और छत्तीसगढ़ को सुपोषित और हरित राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, वि./यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग सकरी, बिलासपुर (छ.ग.)

निविदा निरस्तीकरण आदेश

पत्र क्र. 2625/व.ले.लि./2026-27 बिलासपुर दिनांक 24-07-2026

प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर के पत्र क्र. 4264062/निविदा प्रकोष्ठ / 2026/5234/TC नवा रायपुर दिनांक 23.07.2026 के परिपालन में इस कार्यालय के निविदा सूचना क्र. 02/व.ले.लि./2026-27 दिनांक 12.06.2026 जिला मुंगेली अंतर्गत निर्मित एनीकट / स्टॉपडेम के जलद्वारों का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य (प्रथम आमंत्रण) निविदा सिस्टम क्र. 193060 को निविदा में प्रतिभागी निविदाकार की संख्या एक होने के कारण प्रतिस्पर्धा का अभाव एवं एकल निविदा की स्थिति निर्मित होने के फलस्वरूप निविदा निरस्त किया जाता है।

विज्ञापन क्र. जी 262701424 दिनांक 16.06.2026

कार्यपालन अभियंता
वि./ यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग सकरी बिलासपुर (छ.ग.)

जी-262702367/10

प्रधान की सिर्फ कुर्सी गई राजनीतिक कद बरकरार

नीरज कुमार दुबे

भारतीय राजनीति में संदेश अक्सर शब्दों से नहीं, बल्कि प्रतीकों से दिए जाते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में आज ऐसा ही एक प्रतीकात्मक दृश्य देखने को मिला। दो दिन पहले नीट पेपर लीक विवाद की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान जब संसद पहुंचे तो बीजेपी और एनडीए सांसदों ने उनका स्वागत विजेता की तरह किया। धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारों से संसद परिसर गूंज उठा, पारंपरिक टोपी और शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया और मुस्कुराते हुए प्रधान ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। यहीं से सियासत का नया अध्याय शुरू हो गया। विपक्ष ने सवाल दागा कि क्या यह इस्तीफे का सम्मान था या जवाबदेही का मजाक? कांग्रेस ने इसे उस नेता का महिमामंडन बताया जिसे देश की सबसे बड़ी परीक्षा से जुड़े कथित घोटाले के बाद पद छोड़ना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत समारोह पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने बिलकिस बानो मामले का हवाला देते हुए कहा कि यह उसी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है जिसमें विवादों से घिरे लोगों का भी सार्वजनिक सम्मान किया जाता है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि भाजपा सांसद प्रधान का स्वागत ऐसे किया जा रहा है कि मानो उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। उन्होंने आरोप लगाया कि देश ने पहले भी देखा है कि प्रधान ने अपने इस्तीफे में पेपर लीक के लिए माफी मांगने की बजाय छात्रों पर ही ''गुमराह होने'' का आरोप लगाया था। रमेश ने कहा कि इसके बाद सभी केंद्रीय मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर प्रधान की ''वाहवाही'' की। कांग्रेस महासचिव ने कहा, ''हमारा मानना है कि यह पूरा घटनाक्रम अत्यंत शर्मनाक है और देश के युवाओं का घोर अपमान है। हालांकि बीजेपी के लिए धर्मेंद्र प्रधान केवल पूर्व शिक्षा मंत्री नहीं हैं। वह पार्टी के सबसे भरोसेमंद संगठनकर्ताओं में गिने जाते हैं। ओडिशा में बीजेपी का संगठन खड़ा करने का श्रेय भी काफी हद तक धर्मेंद्र प्रधान को दिया जाता है। 2017 के पंचायत चुनावों से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2024 में बीजेडी को सत्ता से बेदखल कर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत तक, उनकी रणनीति निर्णायक मानी जाती है। अमित शाह के करीबी राजनीतिक प्रबंधकों में उनकी गिनती होती रही है। पार्टी के भीतर उन्हें करिश्माई वक्ता से ज्यादा भरोसेमंद रणनीतिकार और संकटमोचक के रूप में देखा जाता है। लेकिन शिक्षा मंत्रालय का कार्यकाल उनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन अध्याय साबित हुआ। नई शिक्षा नीति, मातृभाषा आधारित शिक्षा और पीएम-श्री स्कूल जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने के बावजूद उनका कार्यकाल लगातार विवादों में घिरा रहा। राष्ट्रीय परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप, एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप, तमिलनाडु के साथ तीन-भाषा फार्मूले पर टकराव, हिंदी थोपने के आरोप और शिक्षा संस्थानों के कथित भगवाकरण को लेकर विपक्ष के हमले लगातार उनका पीछा करते रहे। अंततः नीट विवाद वही मोड़ बन गया जिसने उन्हें पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। देखा जाये तो संसद में धर्मेंद्र प्रधान को मिले सम्मान ने यह संकेत भी दे दिया कि भाजपा उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ने नहीं देना चाहती। माना जा रहा है कि उन्हें जल्द ही पार्टी संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या महासचिव पद की जिम्मेदारी देने के अलावा उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी भी बनाया जा सकता है।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का शाश्वत सियासी संदेश

कमलेश पांडे

केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से कद्दावर ओबीसी नेता धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को केवल भाजपा के एक व्यक्ति का इस्तीफा मानना पर्याप्त नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि वह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नवरत्नों में शुमार किये जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास भी उन्हें हासिल था। बावजूद इसके भारी जनदबाव के बीच यदि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा तो इसे कई स्तरों पर भाजपा/आरएसएस के राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लोकतांत्रिक राजनीति में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रभावी शासन सबसे महत्वपूर्ण पूंजी हैं।

देखा जाए तो जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार कर्नाटक मूल के भाजपा नेता प्रह्लाद जोशी को सौंप दिया है, उसके निहितार्थ को भी समझे जाने की जरूरत है। ऐसा इसलिए कि यह सबकुछ अनायास नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से संपन्न हुआ। थोड़ी नरमी सीजेपी के आंदोलनकारियों यथा- सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके ने दिखाई और थोड़ी भाजपा सरकार के जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जैसे सिपहसालार ने।

वास्तव में, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भारतीय राजनीति में तीन बड़े संदेश देता है—जवाबदेही, जनदबाव की प्रभावशीलता और शिक्षा-युवा मुद्दों की बढ़ती राजनीतिक अहमियत। लेकिन इसके दीर्घकालिक राजनीतिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेंगे कि सरकार परीक्षा प्रणाली में कितने प्रभावी सुधार करती है और विपक्ष इस मुद्दे को कितनी देर तक राजनीतिक रूप से जीवित रख पाता है।

सच कहूं तो 12 वर्षों में पहली बार केंद्र सरकार धर्मसंकट में फंसी थी, इसलिए उसने इंद्रप्रस्थ के इतिहास से सबक लेते हुए धृतराष्ट्र हठ का परित्याग किया और राष्ट्रवादी सूझबूझ प्रदर्शित किया। क्योंकि छात्र आंदोलन और जनदबाव को शांत करना, संसद और विपक्ष के साथ टकराव कम करना, शिक्षा मंत्रालय में नई शुरुआत का संदेश देना और सरकार की व्यापक राजनीतिक छवि को होने वाले नुकसान को सीमित करना, उसका तात्कालिक कर्तव्य समझा गया। जो एक हदतक सही भी है।

जानकारों की मानें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्र आंदोलनों, विपक्ष के दबाव और परीक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवालों के बीच आया है। चूंकि अपने पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट कहा कि वे छात्रों का भविष्य प्रभावित नहीं होने देना चाहते और स्थिति का दुरुपयोग न हो, इसलिए उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा।

इस अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि किसी बड़े जनदबाव के बाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, तो यह अनायास नहीं है, बल्कि भाजपा की सोची, समझी व गुनी हुई राजनीति है। इससे भाजपा सहित सभी दलों और सभी सामाजिक समूहों के नेताओं के लिए कुछ स्थायी सीख निकलती है और इसे सभी को समय रहते ही समझना होगा।

जहां तक इस इस्तीफे के राजनीतिक निहितार्थ और मुख्य सियासी संदेश की बात है तो वह निम्नलिखित हैं-

पहला, सरकार की डैमेज कंट्रोल रणनीति: यदि सरकार को लगा कि विवाद पूरे शासन की छवि पर भारी पड़ रहा है, तो किसी एक मंत्री का इस्तीफा देकर व्यापक राजनीतिक नुकसान सीमित करने की कोशिश की जा सकती है। यह संसदीय और राजनीतिक दबाव कम करने की रणनीति भी हो सकती है। चूंकि जनता की अपेक्षाएँ किसी भी जातीय पहचान से बड़ी होती हैं। लिहाजा किसी नेता की जातीय पृष्ठभूमि से अधिक महत्व उसके कामकाज, जवाबदेही और परिणामों का होता है। इसलिए सरकार ने सही वक्त पर सटीक पोस्टमार्टम किया है और विभागीय कचरों तक की सफाई करवा डाली है।

दूसरा, जवाबदेही का संदेश: लगातार छात्र आंदोलनों और परीक्षा विवादों के बीच एक वरिष्ठ मंत्री का इस्तीफा यह संकेत देता है कि बड़े जनदबाव की स्थिति में सरकार राजनीतिक जवाबदेही दिखाने का विकल्प चुन सकती है। क्योंकि जवाबदेही स्वीकार करना कभी-कभी राजनीतिक नुकसान कम कर सकता है। वहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय पर जिम्मेदारी लेना लंबे समय में पार्टी नेतृत्व का भरोसा बढ़ा सकता है।

तीसरा, युवाओं की राजनीतिक शक्ति का संकेत: छात्र आंदोलनों ने यह साफ संदेश दिया कि रोजगार, परीक्षा और शिक्षा जैसे मुद्दे अब राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इससे भविष्य में सरकारें इन विषयों पर अधिक सतर्क रह सकती हैं। चूंकि युवा मतदाता मुद्दा-आधारित राजनीति को महत्व देते हैं। इसलिए रोजगार, शिक्षा, परीक्षा की निष्पक्षता और अवसर जैसे विषय जातीय समीकरणों से ऊपर भी राजनीतिक प्रभाव डाल सकते हैं। युवा मतदाताओं को संदेश कि सरकार जल्द परीक्षा सुधार, पारदर्शिता और दोषियों पर कार्रवाई करती है। ऐसा करके उसने राजनीतिक नुकसान कम करने की पहल की है। क्योंकि केवल इस्तीफा पर्याप्त नहीं होगा।

चौथा, सरकार ने जनदबाव को स्वीकार किया: लंबे समय बाद किसी बड़े केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा सार्वजनिक दबाव के बाद हुआ है। इससे यह संदेश गया कि सरकार ने राजनीतिक नुकसान सीमित करने का रास्ता चुना। यदि विशेष रूप से भाजपा के ओबीसी नेताओं या सवर्ण नेताओं की बात करें, जो पार्टी की रीढ़ समझे जाते हैं, तो उन्हें यह समझाने का रणनीतिक प्रयत्न है कि किसी भी नेता को केवल अपनी सामाजिक पहचान पर नहीं, बल्कि सुशासन, संगठन क्षमता और जनविश्वास पर अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता बनानी चाहिए। अन्यथा देर सबेर हुई सार्वजनिक लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ेगी।

पांचवां, विपक्ष को मनोवैज्ञानिक बढ़त: विपक्ष इसे अपनी राजनीतिक जीत और जनदबाव की सफलता के रूप में प्रस्तुत करेगा, जबकि सत्तापक्ष इसे व्यवस्था सुधार और नैतिक जिम्मेदारी के रूप में पेश करने का प्रयास करेगा। वाकई यह विपक्ष के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त है, क्योंकि विपक्ष इसे अपनी जीत बताएगा और भविष्य के आंदोलनों में इसे उदाहरण के रूप में पेश करेगा। सवाल है कि क्या यह विपक्ष के सामने घुटने टेकने की शुरुआत है? तो ऐसा निष्कर्ष अभी निकालना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह तभी कहा जा सकेगा जब सरकार भविष्य में भी हर बड़े आंदोलन पर इसी प्रकार झुके, या अन्य विवादों में भी लगातार इस्तीफे और नीतिगत बदलाव दबाव में करने पड़े।

छठा, भाजपा के लिए आंतरिक संदेश: चूंकि संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। इसलिए आसन्न संकट आने पर केवल राजनीतिक संदेश नहीं, बल्कि प्रशासनिक समाधान भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। लिहाजा यह संकेत भी माना जा सकता है कि संगठन और सरकार, दोनों स्तरों पर प्रदर्शन और सार्वजनिक धारणा का महत्व बढ़ गया है। वस्तुतः भाजपा इसे जवाबदेही के संदेश में बदलने की कोशिश करेगी। इसलिए सरकार यह तर्क दे सकती है कि व्यक्ति नहीं, व्यवस्था सर्वोपरि है और सुधारों के लिए जवाबदेही तय की गई है।

यदि आप इस इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी जानना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने आखिर किसके कहने पर अपना इस्तीफा दिया, तो अभी तक सरकार, उसके शीर्ष रणनीतिकार कार्यालय (HMO), संतुलनकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) या भाजपा और उसकी मार्गदर्शक आरएसएस की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है कि आखिर यह निर्णय किस व्यक्ति के निर्देश पर लिया गया। क्योंकि जिस तरह से यूजीसी बिल पर सवर्णों ने धर्मेंद्र प्रधान का सार्वजनिक विरोध किया था, वह भाजपा के भीतर उनकी उल्टी गिनती की शुरुआत समझी गई। स्वाभाविक है कि प्रधान के इस्तीफे से सवर्ण युवाओं में खुशी की लहर है।

उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर सिर्फ कुछ बातें ही कही जा सकती हैं। वह यह कि धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई (शनिवार) को अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा और इसे सार्वजनिक भी किया। खास बात यह कि उनका यह कदम सरकार और आंदोलनकारी पक्ष के बीच तीसरे दौर की वार्ता से ठीक पहले आया। हालांकि यह कहना कि इस्तीफा किसी एक गुट के दबाव में हुआ, उपलब्ध सार्वजनिक साक्ष्यों से सिद्ध नहीं होता। स्वयं धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में कहा कि उनका उद्देश्य छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना और आंदोलन का राजनीतिक दुरुपयोग रोकना था।

इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनका इस्तीफा स्वीकार जाना यह जताता है कि ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय सामान्यतः प्रधानमंत्री और भाजपा/संघ के शीर्ष नेतृत्व की सामूहिक राजनीतिक रणनीति के तहत होता है।

पुराण दिग्दर्शन ....

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

पौराणिक भूगोल के पारिभाषिक शब्द

यूं तो सभी विषयों में कुछ खास खास शब्द ग्रन्थकार के व्यापक अभिप्राय को प्रकट कर सकने के लिए निश्चित रहते हैं जिन्हें कि तत्तत् शास्त्र के परिभाषिक शब्दों के नाम से स्मरण किया जाता है, परन्तु भूगोल विषय में तो पारिभाषिक शब्दों का इतना बाहुल्य है कि तत्सम्बन्धी प्रत्येक भाव को व्यक्त करने लिये बार बार उनके प्रयोग की ही आवश्यकता पड़ती है। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि पौराणिक भूगोल विद्या का अध्ययन करने वाले महानुभावों को सर्व प्रथम पारिभाषिक शब्दों का खूब मनन करना चाहिये।

इस विषय में इतनी बात और भी गाँठ बाँध लेनी चाहिये कि पारि-भाषिक शब्दों की अर्थ सीमा निर्धारित करना ग्रन्थकार की अपनी इच्छा पर ही निर्भर है। वह जिस शब्द को जिस सीमा तक व्यापक करना चाहे यथेच्छ कर सकता है। इस विषय में किसी दूसरे का यह बलात्कार नहीं चल सकता कि वह ऐसा ही क्यों मानता है। हमारी यह उक्ति साधारणतया समस्त पारिभाषिक शब्दों पर और विशेषतथा नाप तोल के परिमाणों (पैमानों Measure) पर सर्वथा लागू होती है जिसकी स्पष्टता के लिये हम यहां कतिपय उदाहरण दे देना भी आबश्यक समझते हैं।

सभी जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु का वजन प्रकट करने के लिये छटाँक, सेर और मन आदि तोल का उल्लेख होता है, परन्तु देश भेद से यह परिमाण पचासों प्रकार का देखा जाता है जैसा कि नीचे लिखी तालिका से विदित हो सकेगा कि सेर की परिभाषा प्रान्त भेद से किस तरह बदल जाती हैं, यथा-

बम्बई शहर में- मेवा, किराना, सागसब्जी और धी का 28 तोले का सेर।

क्रमशः ...

ईश्वर चंद्र विद्यासागर

योगेश कुमार गोयल

बंगाल पुनर्जागरण के प्रमुख स्तंभ तथा नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को समाज सुधारक, दार्शनिक, शिक्षाविद्, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक इत्यादि अनेक रूपों के स्मरण किया जाता रहा है। उन्होंने न केवल नारी शिक्षा के लिए व्यापक जनान्दोलन खड़ा किया बल्कि उन्हीं के अनथक प्रयासों तथा दृढ़संकल्प के चलते ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करने को विवश हुए थे। उसी के बाद भारतीय समाज में विधवाओं को नए सिरे से जीवन की शुरूआत कर ससम्मान जीने का अधिकार मिला था। उनके अथक प्रयासों से ही कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर कई बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई थी और उन्होंने कलकत्ता में मेट्रोपोलिटन कॉलेज की स्थापना भी की थी।

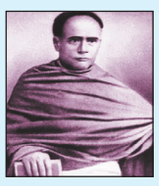

'अपना काम स्वयं करो' सिद्धांत के प्रवर्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अपने क्रियाकलापों से उन्होंने लोगों को हमेशा स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की सीख दी। अपने समाज सुधार अभियान के तहत उन्होंने स्थानीय बांग्ला भाषा तथा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूलों की एक श्रृंखला के साथ कलकत्ता में मेट्रोपोलिटन कॉलेज की स्थापना भी की थी। नारी शिक्षा के लिए गंभीर प्रयास करते हुए उन्होंने बैठुने स्कूल की स्थापना की तथा कुल 35 स्कूल खुलवाए, जिनके संचालन के लिए पूरे खर्च की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं अपने कंधों पर ली। स्कूलों के खर्च के लिए वह विशेष रूप से स्कूली बच्चों के लिए बंगाली में लिखी गई किताबों की बिक्री से फंड जुटाते थे।

समाज सुधार कार्यों की बदौलत उन्हें जीवन पर्यन्त गरीबों और दलितों का संरक्षक माना जाता रहा। अपने इसी प्रकार के समाज की भलाई के लिए किए जाने वाले कार्यों के चलते ही उन्हें एक समाज सुधारक के रूप में जाना जाने लगा था। सदैव समाज की भलाई के लिए ही सोचने और समाज के लिए कुछ न कुछ नया करते रहने के कारण ही नैतिक मूल्यों के संरक्षक विद्यासागर को महान समाज सुधारक के रूप में राजा राममोहन राय का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। ब्रिटिश शासनकाल में ऐसे कॉलेज विरले ही होते थे, जिनका संचालन पूर्ण रूप से भारतीयों के ही हाथों में हो और जहां पढ़ाने वाले सभी शिक्षक भी भारतीय ही हों किन्तु ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सन् 1872 में कोलकाता में विद्यासागर कॉलेज की स्थापना कर यह कारनामा भी कर दिखाया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वास्तव में एक ऐसी महान शख्सियत थे, जिन्होंने न केवल नारी शिक्षा के लिए व्यापक जनान्दोलन खड़ा किया बल्कि अंग्रेजों को विधवा पुनर्विवाह कानून पारित कराने को भी विवश किया। उन्हीं की बदौलत विधवाओं को समाज में सम्मान से जीने का अधिकार मिला। दरअसल उस समय हिन्दू समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत चिंताजनक थी। इसीलिए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत तैयार किया और उनके इन अटूट प्रयासों की बदौलत ही 'विधवा पुनर्विवाह कानून' पारित हो सका। 29 जुलाई 1891 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस दुनिया को अलविदा कह गए किन्तु देश-समाज के लिए किए उनके कार्य आज भी प्रासंगिक है।

बांग्लादेशी पीएम को ब्रिक्स सम्मेलन में न्योता के राजनीतिक मायने

अरुणिम भूयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। यह इस साल फरवरी में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के सत्ता में लौटने के बाद, दोनों पड़ोसी देशों के बीच एक सतर्क राजनयिक संबंधों की शुरुआत का संकेत हो सकता है।

यह निमंत्रण ऐसे समय में आया है जब भारत, ढाका में नई राजनीतिक व्यवस्था के साथ तालमेल बिठा रहा है और बांग्लादेश अपने बाहरी संबंधों को नए सिरे से तय कर रहा है। यह निमंत्रण दोनों पक्षों को अतीत की राजनीतिक अनिश्चितताओं से आगे बढ़ने और सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता में साझा हितों के इर्द-गिर्द संबंधों को फिर से बनाने का अवसर प्रदान करता है।

भारतीय पक्ष से निमंत्रण मिलने की पुष्टि करते हुए, बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने गुरुवार को कहा कि इसे प्रधानमंत्री रहमान के कार्यालय को भेज दिया गया है।

ढाका ट्रिब्यून समाचार वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार, ढाका में मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार वाला एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते, इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता देखना चाहता है। उनके हवाले से कहा गया, यह हमारा रुख है, और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे।

ब्रिक्स एक प्रमुख अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। हाल ही में इसका विस्तार किया गया- जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया को शामिल किया गया है। यह ब्लॉक वैश्विक आबादी का लगभग 50 प्रतिशत और दुनिया की जीडीपी के 40 प्रतिशत से अधिक का

प्रतिनिधित्व करता है।

इस साल नई दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रमुख विश्व नेताओं में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल होने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के मेजबान के रूप में, भारत ब्लॉक से बाहर के देशों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकता है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि रहमान के अलावा, भारत ने बिम्सटेक (BIMSTEC) क्षेत्रीय ब्लॉक के सदस्य देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है।

बांग्लादेश को दिए गए पीएम मोदी के इस निमंत्रण का महत्व केवल एक बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन में रहमान की संभावित भागीदारी तक ही सीमित नहीं है। यह नई दिल्ली द्वारा बीएनपी सरकार के साथ एक सीधा राजनीतिक संपर्क स्थापित करने का प्रयास है। जिसने शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार की जगह ली है, जिसके साथ भारत ने एक दशक से अधिक समय में बेहद करीबी संबंध विकसित किए थे। पीएम मोदी ने बीएनपी की चुनावी जीत को स्वीकार करने में तेजी दिखाई थी, रहमान को बधाई दी थी। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने व साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत की तत्परता व्यक्त की थी।

इस पृष्ठभूमि में, रहमान को एक बड़े अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में नई दिल्ली आमंत्रित करना यह संकेत दे सकता है कि भारत राजनीतिक संबद्धताओं के बजाय देश-से-देश के हितों के आधार पर नई सरकार के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। यह बीएनपी के सत्ता में आने के बाद से पीएम मोदी और रहमान के लिए भारत में पहली बड़ी आमने-सामने की विस्तृत चर्चा करने का अवसर भी प्रदान कर सकता है।

अवामी लीग से बीएनपी में सत्ता का यह बदलाव भारत-बांग्लादेश संबंधों के राजनीतिक संदर्भ को पूरी तरह बदल चुका है। नई दिल्ली के लिए, शेख हसीना की सरकार आतंकवाद विरोध और सीमा प्रबंधन से लेकर कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय एकीकरण जैसे मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण भागीदार थी। इसलिए, सरकार बदलने से द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य के रास्ते को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई थी।

रहमान के उदय ने एक चुनौती और अवसर दोनों पेश किए हैं। ऐतिहासिक रूप से बीएनपी के भारत के साथ संबंध अवामी लीग की तुलना में अधिक जटिल रहे हैं, जबकि बीएनपी से जुड़े राजनीतिक दलों ने अलग-अलग समय पर एक अधिक विविधतापूर्ण विदेश नीति की वकालत की है। नतीजतन, नई दिल्ली के पास सतर्क रहने के कई कारण हैं। खासकर सुरक्षा, अल्पसंख्यक अधिकार, सीमा पार उग्रवाद और बांग्लादेश में चीनी प्रभाव के संभावित विस्तार को लेकर।

फिर भी, भारत की ओर से शुरुआती संकेत व्यावहारिक रहे हैं। ब्रिक्स का यह निमंत्रण उसी जुड़ाव की नीति का एक हिस्सा प्रतीत होता है। यह दर्शाता है कि नई दिल्ली नहीं चाहती कि ढाका में आए इस राजनीतिक बदलाव के कारण दोनों देशों के बीच लंबे समय तक राजनयिक गतिरोध बना रहे या रणनीतिक दूरियां बढ़ें।

यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि इस साल अप्रैल में, बीएनपी सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद, भारत ने अनुभवी राजनीतिज्ञ दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया था। यह इस बात का संकेत है कि नई दिल्ली, ढाका को एक सामान्य विदेशी पोस्टिंग के बजाय एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील और प्राथमिकता वाले पड़ोसी देश के रूप में देखता है।

ऐसी नियुक्तियां बहुत कम होती हैं और आमतौर पर रणनीतिक रूप से संवेदनशील पदों के लिए सुरक्षित रखी जाती हैं। एक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति को भेजकर, नई दिल्ली ने यह संकेत दिया है कि बांग्लादेश उसकी विदेश नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। इस रिश्ते को उच्चतम स्तर से राजनीतिक देखरेख की आवश्यकता है, और नई दिल्ली संबंधों को स्थिर व मजबूत करने के लिए राजनीतिक पूंजी लगाने के लिए तैयार है।

इस निमंत्रण द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भारत, बांग्लादेश में बीएनपी सरकार को वहां की वैध राजनीतिक सत्ता के रूप में सीधे स्वीकार करने और उसके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है।

यह विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच बेहद करीबी व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंध विकसित हो गए थे। साल 2024 में अवामी लीग सरकार के पतन ने द्विपक्षीय संबंधों में एक कठिन दौर पैदा कर दिया था। जिससे नई दिल्ली में राजनीतिक अस्थिरता, अल्पसंख्यकों पर हमले, भारत-विरोधी बयानों और बांग्लादेश के रणनीतिक झुकाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं।

नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन में रहमान को आमंत्रित करके, भारत यह संकेत दे रहा है कि वह शेख हसीना के दौर से आगे बढ़ने और नए नेतृत्व के साथ कामकाजी संबंध बनाने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह नहीं है कि नई दिल्ली अपनी चिंताओं को छोड़ देगी या विवादास्पद मुद्दों को नजरअंदाज करेगी। इसके बजाय, यह दर्शाता है कि भारत उन चिंताओं को सीधे बातचीत के जरिए सुलझाने को प्राथमिकता दे रहा है।

हसीना के दौर के बाद, भारत और बांग्लादेश के नेतृत्व के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंधों की कमी एक बड़ी चुनौती रही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस दूरी को पाटने में मदद कर सकता है।

आज का इतिहास

1957 संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) का गठन किया।

1958 अमेरिकी कांग्रेस ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) की स्थापना के लिए विधेयक पास किया।

1967 वियतनाम युद्ध के दौरान, टोंकिन की खाड़ी में एक और हड़ताल की तैयारी के दौरान, विमानवाहक पोत यूएसएस फॉरेस्टल को इसके डेक डेक पर एक असामान्य विद्युत विसंगति की वजह से कई तरह के रिएक्शन विस्फोट हुए, जिससे 134 नाविक मारे गए और 161 अन्य घायल हो गए।

1981 ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स और राजकुमारी डायना की शादी हुई। उस वक्त लगभग 70 करोड़ लोगों ने टीवी पर इस शाही शादी को देखा।

1983 पहले चालक रहित विमान मिनी ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी।

1993 इजरायल कोर्ट ऑफ अपील ने जॉन डेमजॉजुक के विश्वास को (5-0) पलट दिया। इसने कहा है कि वह पर्याप्त प्रमाण नहीं है, एकाग्रता शिविर इवान द टेरिबल।

1995 कैरोलिना पैंथर्स ने जैक्सनविले जगुआर को हराया है। उन्होंने अपने प्रथम एनएफएल प्रदर्शनी खेल 20-14 में हराया। यह उसके लिए एक बड़ी सफलता थी।

2010 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के कसई नदी बंडुंडु प्रांत में एक अतिभारित यात्री फेरी की वजह से कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई।

2011 ऋण सीमा को बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने मतदान किया है। लेकिन सीनेट ने इसे स्वीकार नहीं किया और उपाय को खारिज कर दिया।

2012 वैज्ञानिकों द्वारा एक तंत्र की पहचान की जाती है। यह पृथ्वी-वार्मिंग कार्बन को दक्षिणी महासागर में गहरे खींच लेगा और लॉक कर देगा। वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि इस प्रक्रिया से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है।

2012 चीन में हांगकांग के स्कूल में राष्ट्रीय देशभक्ति का पाठ पेश किया जाएगा। हजारों विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने इसे चीनी प्रचार का लेबल लगाने की वकालत की।

2013 फ्रांस के कांस के एक होटल से 10.3 करोड़ यूरो के हीरे की चोरी हुई।

2013 फ्रांस के कान्स में कार्लटन इंटरकांटिनेंटल होटल के डायमंड शो से हीरे और अन्य गहने में लगभग 103 मिलियन यूरो चोरी हो गए। यह वर्तमान वर्षों में सबसे बड़े गहने चोरी में से एक है।

भारत की शिक्षा व्यवस्था को नौकरशाही में फेरबदल नहीं, प्रणालीगत सुधारों की जरूरत

शेखर गुप्ता

नरेंद्र मोदी सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं के बीच सीधी बातचीत हुई, सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है और प्रदर्शनकारियों को मनाने के लिए नाटकीय कदम उठाते हुए गुरुवार देर रात उच्च शिक्षा सचिव को पद से हटा दिया गया। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे और वे इस कदम से संतुष्ट नहीं हुए। अब तो प्रधान का इस्तीफा भी हो चुका है और जंतर मंतर से प्रदर्शनकारी भी लौट चुके हैं।

मगर उच्च शिक्षा सचिव को पद से हटाए जाने पर मुझे अपने दफ्तर की दीवार पर टंगा छोटा सा फ्रेम याद आ गया। वह मुझे अपनी बेटी से उपहार में मिला 1942 की मशहूर फिल्म कैसाब्लांका का पोस्टर है। भले ही आपने यह फिल्म न देखी हो, लेकिन आपको वह अमर संवाद जरूर याद होगा, जिसमें कैप्टन लुई रेनो एक घातक गोलीबारी के बाद पुलिसकर्मियों से कहते हैं, 'पुराने संदिग्धों को पकड़ लाओ।' सचिवों के तबादले भी कुछ वैसे ही हैं।

किसी भी संकट में अफसरशाह आसान शिकार बन जाते हैं। 2024 में नीट पेपर लीक के बाद भी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) में छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस और महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह समेत कुछ अहम लोगों को हटाया गया था। नेताओं को यही सहज लगता है। उच्च शिक्षा सचिव पद से हटाकर पंचायती राज सचिव बनाए गए विनीत जोशी एनटीए के पहले महानिदेशक थे।

मोदी सरकार के काम करने के तरीके और पुराने रिकॉर्ड को देखकर प्रधान का हटना असंभव लग रहा था क्योंकि किसानों के आंदोलन में झुक जाने के बाद अब वह दबाव में मान जाने वाली सरकार की छवि नहीं चाहती थी। बहरहाल प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और प्रदर्शनकारी संतुष्ट होकर घर लौट गए मगर क्या इससे भारत के युवाओं का संघर्ष खत्म हो जाएगा? भारत में बचपन आज इतना तनाव भरा, होड़ भरा और एकांगी (सिर्फ पढ़ाई और परीक्षा तक सीमित) हो गया है, जितना पहले कभी नहीं था।

नीट को ही देखिए। इस वर्ष 22 लाख छात्रों ने परीक्षा दी। एमबीबीएस की 1,39,489 सीटों के लिए इनमें से केवल 5 प्रतिशत ही चुने गए। उनके अलावा 25,000 से 35,000 छात्र एमबीबीएस करने के लिए विदेश जाएंगे, जिनमें ज्यादातर पूर्व सोवियत गणराज्यों, फिलिपींस और बांग्लादेश तक में पढ़ेंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर वे भारत में डॉक्टर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो उन्हें भी नीट (50 पर्सेंटाइल के कट-ऑफ से ऊपर) निकालना पड़ता है। इस सबके बीच 20 लाख से अधिक छात्र दौड़ से बाहर रह जाते हैं। इनमें से कई ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े कॉलेजों में प्रवेश के लिए सीयूईटी (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) भी दिया होगा। लेकिन वहां भी चयन की संभावना बहुत कम है। लाखों छात्र इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए जेईई की होड़ में हैं। पहली सीढ़ी लांघने के बाद भी छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं

का सिलसिला खत्म नहीं होता। स्नातकोत्तर हो, पीएचडी हो या अध्यापन की नौकरी, हर बार परीक्षा आ जाती है। मध्यमवर्गीय या उससे कम आय वाले भारतीय परिवारों के बच्चों का जीवन 15 वर्ष की उम्र से ही कोचिंग संस्थानों, प्रतियोगी परीक्षाओं और पेपर लीक होने पर दोबारा परीक्षाओं के अंतहीन चक्र में फंस जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जंतर-मंतर पर इतने अधिक छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? उनमें से कई के तो माता-पिता भी आए थे। इन बच्चों के पास शौक पूरे करने या खेलकूद के लिए वक्त ही नहीं बचता। फिर हम पूछते हैं कि भारत खेलों में अच्छा क्यों नहीं कर पाता। बच्चा खेलकूल में लगे तो माता-पिता को लगता है कि वह अपना भविष्य 'बरबाद' कर रहा है।

इसे समझने के लिए देश के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट का ढांचा देखिए, जहां हमें विश्वस्तरीय प्रतिभाएं मिल रही हैं। तीनों तरह की भारतीय टीम, आईपीए और स्थानीय लीग तक की टीमें शायद ही कभी किसी कॉलेज स्नातक को मैदान में उतारती हैं। ये प्रतिभाएं कक्षा 10 में ही चुन ली जाती हैं। वैभव सूर्यवंशी इसका उदाहरण हैं।

हमारी शिक्षा प्रणाली सभी प्रतिभाओं की खत्म कर देती है। वह पहले रटकर सीखने पर मजबूर करती है और फिर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाएं निकालने के लिए कोचिंग क्लासों में धकेलती है। इस तरह हम ऐसी पीढ़ी बना रहे हैं जो खुद को उपेक्षित और ठगा हुआ महसूस करती है। एक मंत्री को हटाने भर से स्थिति नहीं सुधरेगी। इस व्यवस्था को पूरी तरह उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। लेकिन यह असंभव सा लगता है क्योंकि यह 'मजबूत' सरकार की विचारधारा से मेल नहीं खाता। आखिर दिल्ली में 'मजबूत' सरकार का क्या मतलब है अगर सब कुछ उसके अधीन नहीं हो।

आपको लगता होगा कि मोदी सरकार से पहले नीट पेपर लीक की दिक्कत क्यों नहीं थी। जवाब है, तब नीट था ही नहीं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) ने भी मेडिकल में प्रवेश को केंद्रीकृत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बनाए नीट को 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के पीठ ने 2-1 से असंवैधानिक बता दिया। कई राज्यों खासकर दक्षिण के राज्यों ने इसे अपने संघीय अधिकार की चोरी माना।

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने 2010 में नीट की स्थापना निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पर पिछले दरवाजे से नियंत्रण के लिए ही की थी। बाद में 2013 के अदालती आदेश को चुनौती दी गई और उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के पीठ ने 2016 में उसे पलट दिया। अब नीट न्यायालय द्वारा अधिकृत संस्था बन गई।

केंद्रीकरण का विचार संप्रग युग की समाजवादी सोच से आई थी ताकि निजी मेडिकल कॉलेजों में ऊंची कैपिटेशन फीस खत्म की जा सके। अगर वे तय ही नहीं कर पाएंगे कि किसे प्रवेश देना है तो वे भारी-भरकम फीस कैसे वसूलेंगे? इस हिसाब से यह मेडिकल शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की तरह था। चूंकि दक्षिण भारत और महाराष्ट्र मेडिकल शिक्षा में आगे थे, इसलिए एमसीआई और केंद्रीय तंत्र ने नए मेडिकल कॉलेजों के लिए आबादी के हिसाब से लाइसेंसिंग लागू करके उद्योग को दबाने की कोशिश की। इसमें प्रति 10 लाख आबादी पर एक ही मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस दिया जाना था। दक्षिणी राज्यों और महाराष्ट्र ने विरोध किया और इसे रद्द कर दिया गया। रद्द इसलिए भी हुआ क्योंकि कई कॉलेज राजनेताओं के स्वामित्व में हैं जिनमें सत्तारूढ़ दल और उसके सहयोगी दलों के नेता भी हैं।

नीट से पहले राज्य अपनी अलग प्रवेश परीक्षाएं कराते थे और लाखों स्कूली बच्चे इस राष्ट्रीय तनाव से बचे हुए थे। केंद्र सरकार को भी इतने बड़े स्तर पर परीक्षा कराने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता था। मगर वर्तमान केंद्र सरकार सब कुछ अपनी मुट्ठी में चाहती है। अब वे नया कानून ला रहे हैं ताकि पूरे देश में उच्च शिक्षा पर उनका नियंत्रण और बढ़ जाए। गूगल पर विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 ढूंढिए। इसमें व्यापक अधिकरों वाले उच्च शिक्षा आयोग और तीन नियामक परिषदों का प्रस्ताव है। यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को खुद में समेटकर विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा की निगरानी ये ही करेंगे। शुक्र है कि स्थायी समिति ने अभी इसे रोक दिया है।

नीट पर लौटें तो इस केंद्रीकरण की सफलता को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एनटीए बना दी। इसका काम नीट, जेईई, यूजीसी-नेट और सीयूईटी (स्नातक एवं स्नातकोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश) आयोजित करना है।

महज एक 'सोसाइटी' के लिए यह बहुत ज्यादा अधिकार है चाहे इसका नेतृत्व विचारधारा में निष्ठा रखने प्रदीप कुमार जोशी ही क्यों न कर रहे हों। वे शिक्षा जगत के हैं आईएएस नहीं। उनका रिकॉर्ड देखें- मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष (2006 से 2011), छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (2011 से 1015), संघ लोक सेवा आयोग (2020 से 2022) और अब एनटीए। ऐसे अधिकार और राजनीतिकरण से गड़बड़ तय थी और मोदी सरकार ने यह आफत खुद मोल ली है।

इससे पहले 47 अधिकारियों को पद से हटा दिया गया। मोदी सरकार भारी केंद्रीकरण की यह कीमत चुका रही है। जब भी संकट आता है, सरकार नए कानून का झुनझुना थमा देती है। नीट परीक्षा में धोखाधड़ी के खिलाफ अलग से कानून बना दिया है मानो आम धोखाधड़ी का कानून उस पर लागू नहीं होगा। इसके लिए विशेष अदालत बना दी हैं, जो वर्षों तक चलती रहेंगी।

जेन जी: रील-बाज बनाम रियल आवाज

विवेक दत्त मथुरिया

इतिहास गवाह है कि जब-जब किसी पीढ़ी को सतही, दिशाहीन और गैर-संवेदनशील मानकर खारिज किया गया, उसने अपनी पूरी ताकत के साथ वापसी करके दुनिया को चौंकाया है। भारत की 'जेन जी' यानी इंटरनेट, स्मार्टफोन और 15-सेकंड की रील्स के दौर में बड़ी हुई पीढ़ी के साथ भी यही पूर्वाग्रह पाला गया। सत्ता के गलियारों, राजनीतिक विश्लेषकों और खुद अभिभावकों के ड्राइंग रूम्स में यह धारणा आम थी कि यह पीढ़ी केवल स्क्रीन स्क्रॉल करने, फिल्टर लगाने और रील बनाने में मस्त है लेकिन दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ 35 दिनों तक चला अनुशासित, अहिंसक और अडिग आंदोलन इस पूर्वाग्रह के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ है। इस आंदोलन ने न केवल सियासी पंडितों के आंकड़ों को झुठलाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जेन जी का डिजिटल अवतार केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की ढाल भी है। पारंपरिक आंदोलनों का तरीका अब बदल चुका है, जहाँ पुरानी पीढ़ियाँ राजनीतिक झंडों, ट्रेड यूनियनों और स्थापित नेताओं के सहारे सड़कों पर उतरती थीं। वहीं जेन जी ने बिना किसी स्वघोषित रहनुमा के अपने संघर्ष को खड़ा किया। सोशल मीडिया—जिसे सत्ता और समाज ने समय की बर्बादी का पर्याय मान लिया था, उसी को इस आंदोलन का मुख्य वॉर-रूम बनाया गया। इंस्टाग्राम, लाइकस, एक्स (ट्विटर) हैश टैग्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए न केवल दूर-दराज के छात्रों को आंदोलित किया गया। बल्कि आंदोलन के खर्चों से लेकर कानूनी सलाह तक की हर जानकारी पारदर्शी तरीके से सामने रखी गई। सच यह है कि इस पीढ़ी ने सिद्ध कर दिया कि ये केवल रील-बाज ही नहीं, बल्कि रियल आवाज़ हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति से नागरिक चेतना तक पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनिश्चितता ने देश के लाखों युवाओं की सालों की तपस्या पर पानी फेर दिया। मेहनत का फल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने लगा, तो यह आक्रोश सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि भविष्य के अस्तित्व का सवाल बन गया। इस पीढ़ी ने दिखाया कि वे भले ही आधुनिक उपभोक्तावादी दौर का हिस्सा हों, लेकिन जब उनके संवैधानिक अधिकारों पर चोट होती है, तो उनकी नागरिक चेतना किसी भी अन्य पीढ़ी से कमज़ोर नहीं पड़ेगी। 35 दिनों तक बिना किसी हिंसा, बिना किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाए शांतिपूर्वक तार्किक बहसों के साथ डटे रहना इस बात का सबूत है कि यह आंदोलन भावुकता का नहीं, बल्कि परिपक्व समझ का नतीजा था। राजनीतिक दलों के लिए यह आंदोलन एक बहुत बड़ा सबक है। राजनीति अब तक युवाओं को केवल वोट बैंक या चुनावी रैलियों में भीड़ के रूप में इस्तेमाल करती आई है लेकिन जेन जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे खोखले नारों, मुफ़्त की घोषणाओं या पुरानी पहचान-आधारित राजनीति से बहलने वाले नहीं हैं, उन्हें पारदर्शी व्यवस्था, रोजगार और सम्मानजनक भविष्य चाहिए। अगर सरकारें और नीति-निर्माता अब भी इस पीढ़ी की खामोशी या उनके रील बनाने को उनकी कमज़ोरी समझेंगे, तो यह उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी। जंतर-मंतर का 35 दिवसीय आंदोलन महज़ एक विरोध-प्रदर्शन नहीं था, यह भारत की युवा पीढ़ी का आत्म-घोषणापत्र था। इस आंदोलन ने उस धारणा को ध्वस्त कर दिया है, जो इन्हें नकारा या निकम्मा मानती थी। जेन जी ने साबित कर दिया है कि वे स्क्रीन पर उंगलियां चलाने में जितने माहिर हैं, लोकतंत्र की ज़मीन पर अपने हक के लिए खड़े होने में उतने ही निर्भीक हैं। अब वक्त आ गया है कि सत्ता, समाज और सियासी पंडित अपने चश्मे का नंबर बदलें। जेन जी रील्स की दुनिया से बाहर निकलकर व्यवस्था के पन्नों पर अपना इतिहास लिखने की शुरुआत कर चुकी है।

'छात्र आंदोलन': इसे सावधानी से संभालने की आवश्यकता

कल्याणी शंकर

मई में अपनी शुरुआत के बाद से, कॉकरोच जनता पार्टी (सी.जे.पी.) एक महत्वपूर्ण आंदोलन में विकसित हो गई है, जिसने कई व्यक्तियों और विभिन्न विपक्षी समूहों का ध्यान आकर्षित किया है। यह भारत के युवाओं के बीच असंतोष की एक शक्तिशाली आवाज बन गई है, जो विभिन्न मुद्दों पर सरकार को चुनौती दे रही है। सी.जे.पी. ने गति पकड़ी है और कई लोगों को प्रेरित किया है, जो भारतीय राजनीति में इसके महत्व को उजागर करता है। यह भारत में सबसे प्रमुख युवा आंदोलनों में से एक के रूप में खड़ा है, जो सरकार के खिलाफ सार्वजनिक विरोध का प्रतिनिधित्व करता है।

'कॉकरोच' विरोध प्रदर्शन मैडीकल कॉलेजों और सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के चिंताजनक दावों के जवाब में शुरू किया गया था। शुरुआत में इन विशिष्ट परीक्षाओं पर केंद्रित, यह जल्द ही एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल गया। अब, इसमें न केवल सीधे प्रभावित छात्र, बल्कि पेशेवर, माता-पिता और आम नागरिक भी शामिल हैं, जो देश में आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को लेकर निराशा सांझी करते हैं। आंदोलन का नाम भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई एक टिप्पणी से उपजा है, जिन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। सी.जे.पी. ने इस अपमान को लिया और इसे युवाओं के लिए एक ललकार में बदल दिया। कार्यकर्त्ता सोनम वांगचुक विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए और खुद को 'मानद कॉकरोच' बताया। उन्होंने नई दिल्ली में शांतिपूर्वक जागरूकता बढ़ाने के लिए 26 दिन तक भूख हड़ताल भी की। अपने अस्पताल के बिस्तर से एक वीडियो में, उन्होंने कहा कि उन्हें लिखित आश्वासन मिला है कि सरकार परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करेगी और विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले युवाओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

यह आंदोलन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, साथ ही भविष्य में लीक को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर था।

उन्होंने इन मुद्दों से प्रभावित छात्रों के लिए मुआवजे की भी मांग की, जो वास्तविक बदलाव के लिए उनकी इच्छा को उजागर करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि परीक्षा पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों से निपटने के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी, जो विवाद पर उनकी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जोर दिया कि युवाओं का कल्याण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सी.जे.पी. की स्थापना अभिजीत दीपके ने की, जो बेरोजगार युवाओं के बारे में मुख्य न्यायाधीश की अपमानजनक टिप्पणियों को सुनने के बाद कार्य करने के लिए प्रेरित हुए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में सवाल किया, ''क्या होगा अगर सभी कॉकरोच एक साथ आ जाएं?'' जैसे-जैसे परीक्षा लीक के और आरोप सामने आए, सार्वजनिक विरोध तेज होता गया। ये परीक्षाएं भारत में नौकरी के अवसरों और सामाजिक गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनकी अखंडता के लिए कोई भी खतरा उन छात्रों हेतु महत्वपूर्ण देरी और तनाव का कारण बन सकता है, जो कीमती अध्ययन समय खोने से डरते हैं।

सी.जे.पी. अलग दिखती है क्योंकि यह पारंपरिक राजनीतिक दलों से संबद्ध नहीं है, जो जमीनी प्रयासों में विश्वास और गर्व को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह स्वतंत्रता लोगों को उम्मीद देती है कि युवा व्यक्ति सोशल मीडिया और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से सार्थक बदलाव ला सकते हैं। यह आंदोलन जून में तब चर्चा में आया, जब दीपके अमरीका से लौटे और विभिन्न शहरों और विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, जिसमें सैंकड़ों समर्थक इकट्ठे हुए और राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। जो ऑनलाइन व्यंग्य के रूप में शुरू हुआ, वह युवा निराशा की एक मजबूत अभिव्यक्ति में बदल गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हुए, सार्वजनिक आक्रोश बढ़ गया। राजनीतिक विरोधियों ने संसदीय सत्रों के दौरान आंदोलनकारियों की मांगों को दोहराया है। कुछ बॉलीवुड हस्तियां, जिन्हें इन विरोध प्रदर्शनों पर चुप रहने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था, ने छात्रों की सामूहिक कार्रवाई के समर्थन में बात की, सरकार की सीधे आलोचना किए बिना उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। इनमें आमिर खान, प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान शामिल हैं।

हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शनों को संबोधित नहीं किया लेकिन परीक्षा लीक मुद्दे पर उनकी स्वीकृति से पता चलता है कि वह चिंताओं से अवगत हैं। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि मोदी दबाव में दिख रहे थे और उनके लिए निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें उनके शिक्षा मंत्री को हटाना भी शामिल है। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका सहित विपक्षी नेताओं ने मोदी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जैसा कि उनकी पार्टी ने वीडियो में सांझा किया। ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे अन्य नेता भी सरकार के आलोचक थे। चरमोत्कर्ष तब आया, जब प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। सी.जे.पी. चिल्ला रहा था, ''हम जीत गए हैं।'' जंतर-मंतर पर उनकी भीड़ जल्दी ही तितर-बितर हो गई। क्या यह गलत समय पर सही कार्रवाई है? भारत के मुख्य न्यायाधीश (सी.जे.आई.) का किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और न ही उनकी कोई विशिष्ट विचारधारा है। यह आंदोलन स्वतःस्फूर्त शुरू हुआ, जो एक प्रमुख सार्वजनिक मुद्दे को संबोधित करता है, जो सरकार के लिए एक चुनौती पेश करता है। उन्हें इसे सावधानीपूर्वक संभालने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ भाजपा सदस्य भी 'नीट' को लेकर चिंतित हैं। हमें यह देखने की जरूरत है कि आने वाले महीनों में यह स्थिति कैसे विकसित होती है।

कोलकाता की हिंसा: साजिश या लोकतांत्रिक असहमति का भटकाव?

सत्येंद्र प्रताप सिंह

शिक्षा में कथित भ्रष्टाचार और नीट परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन शुक्रवार को कोलकाता के धर्मतला में ऐसे मोड़ पर पहुंच गया, जहां शिक्षा का सवाल पीछे छूट गया और कानून-व्यवस्था, हिंसा तथा राजनीतिक टकराव केंद्र में आ गए। लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब आंदोलन हिंसक हो जाए, पुलिस और पत्रकार निशाने पर आ जाएं और सार्वजनिक व्यवस्था को चुनौती मिलने लगे, तब यह केवल विरोध नहीं रह जाता, बल्कि उसकी प्रकृति और उद्देश्य दोनों पर सवाल उठने लगते हैं।

शुक्रवार, यानी जुमे की नमाज के दिन आयोजित इस प्रदर्शन के समय और स्वरूप को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। घटनास्थल के वीडियो और तस्वीरों में बड़ी संख्या में ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जिनकी पहचान अब जांच एजेंसियों के लिए कठिन नहीं होगी। यदि जांच में यह साबित होता है कि आंदोलन में ऐसे लोग शामिल थे जिनका छात्र आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, तो यह केवल भीड़ की स्वत:स्फूर्त प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सुनियोजित रणनीति का संकेत भी हो सकता है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष केवल निष्पक्ष जांच के आधार पर ही निकलना चाहिए।

धर्मतला में सीजेपी के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में वामपंथी छात्र संगठनों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राज्य सरकार का आरोप है कि डोरिना क्रॉसिंग पहुंचते ही भीड़ के एक हिस्से ने पुलिस पर जूते और पानी की बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं। उद्देश्य पुलिस को उकसाना था ताकि लाठीचार्ज हो और आंदोलन को राजनीतिक रंग दिया जा सके। मुख्यमंत्री का कहना है कि पुलिस को स्पष्ट निर्देश थे कि किसी भी उकसावे में नहीं आना है और संयम बनाए रखना है। उपलब्ध वीडियो भी संकेत देते हैं कि तनावपूर्ण माहौल के बावजूद पुलिस ने तत्काल बल प्रयोग से

परहेज किया। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चिंताजनक पक्ष पत्रकारों पर हमला रहा। पुलिस के अनुसार मीडिया संस्थानों की ओर से कई शिकायतें दर्ज कराई गईं और कम-से-कम छह पत्रकार घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में उपचार कराना पड़ा।

लोकतंत्र में पत्रकार केवल घटनाओं के दर्शक नहीं होते, बल्कि जनता तक तथ्य पहुंचाने वाले माध्यम होते हैं। यदि किसी आंदोलन में मीडिया को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है, तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था—दोनों के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। राज्य सरकार ने घटना को गंभीर मानते हुए हेयर स्ट्रीट थाने में छह और एंटाली थाने में एक—कुल सात मामले दर्ज कराए हैं। पुलिस ने अवैध जमावड़ा, हिंसा, सरकारी कर्मचारियों के कार्य में बाधा, सार्वजनिक शांति भंग करने और उकसावे जैसी धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं।

एक मामला पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज किया है, जबकि कई शिकायतें मीडिया संस्थानों की ओर से आई हैं। सरकार ने इन मामलों में गुंडा दमन कानून लागू करने का भी निर्णय लिया है, ताकि यदि संगठित आपराधिक तत्वों की भूमिका सिद्ध हो, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि अब तक जिन लगभग 70 लोगों की पहचान की गई है, उनमें से अधिकांश का न तो छात्र संगठनों से कोई संबंध है और न ही नीट आंदोलन से। उन्होंने राजाबागान, खिदिरपुर, एकबालपुर और वाटगंज क्षेत्रों के कुछ कथित कुख्यात अपराधियों के नाम सार्वजनिक करते हुए कहा कि कानून के तहत ऐसी कार्रवाई होगी जिसे अपराधियों की आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। यह गंभीर आरोप है। यदि जांच में इसकी पुष्टि होती है, तो यह स्पष्ट होगा कि किसी वास्तविक जनआंदोलन को असामाजिक तत्वों ने अपने हितों के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया। लेकिन यदि आरोप सिद्ध नहीं होते, तो सरकार को भी अपने दावों का उत्तर देना होगा। इसलिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच ही सबसे महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ वामपंथी छात्र संगठनों की आड़ में ऐसे लोग शामिल हुए जिनकी पहचान छात्र के रूप में नहीं की जा सकती। दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनआंदोलन को दबाने के लिए कठोर कानूनों का सहारा ले रही है। इन आरोप-प्रत्यारोपों के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या राजनीतिक दल अपने आंदोलनों की जवाबदेही स्वीकार करेंगे? किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि वह हिंसक तत्वों से स्वयं को अलग रख सके। घटना का एक सकारात्मक पक्ष पुलिस का संयम भी रहा। यदि वास्तव में पुलिस को उकसाया गया और उसने धैर्य बनाए रखा, तो यह लोकतांत्रिक प्रशासन की परिपक्वता का उदाहरण है। कानून लागू करने वाली एजेंसियों का उद्देश्य केवल बल प्रयोग नहीं, बल्कि न्यूनतम बल के साथ शांति बनाए रखना होना चाहिए। हालांकि यह भी उतना ही आवश्यक है कि यदि किसी पुलिसकर्मी की ओर से कहीं अति हुई हो, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच हो।

शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और परीक्षा प्रणाली जैसे मुद्दों पर जनता का आक्रोश स्वाभाविक है। सरकारों को ऐसे आंदोलनों को केवल कानून-व्यवस्था के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनके मूल कारणों का समाधान भी करना चाहिए।

जंतर-मंतर प्रकरण: आंदोलन का अंत या भविष्य के आंदोलनों की पृष्ठभूमि?

विनोद कुमार विक्की

हफ्तों से चले आ रहे सीजेपी के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में से एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग अंतत: पूरी हो गई। उनके इस्तीफे के बाद सरकार के विरोधियों, सीजेपी, छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने इसे अपनी बड़ी जीत के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि सरकार के समर्थकों ने इसे परिस्थितियों के दबाव में लिया गया निर्णय बताया। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हिंसक प्रदर्शन के सहारे व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंत माना जा सकता है, अथवा इससे भविष्य में उग्र और हिंसक आंदोलनों के माध्यम से अन्य मांगों को मनवाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा? भारतीय संविधान के भाग-3 के अनुच्छेद 19(1)(b) के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को शांतिपूर्ण एवं निरायुध होकर प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है। किंतु इस अधिकार की मर्यादा जंतर-मंतर पर हुए घटनाक्रम के संदर्भ में गंभीर चर्चा का विषय बन गई है। नीट परीक्षा सहित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होना अथवा साठगांठ के माध्यम से परीक्षा में उत्तीर्ण होना किसी भी दृष्टि से छात्रों तथा स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित में नहीं है। निष्पक्ष परीक्षाओं को कलंकित करने वाले तथा प्रश्नपत्र लीक प्रकरण में संलिप्त कर्मियों, पदाधिकारियों अथवा माफियाओं पर दया करना या उन्हें संरक्षण देना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। वहीं दूसरी ओर, इन सबका विरोध करने का माध्यम उग्र हिंसा, भड़काऊ बयानबाजी अथवा धर्मविरोधी गतिविधियां भी लोकतंत्र के हित में नहीं हैं। जंतर-मंतर से कई ऐसे दृश्य सामने आए हैं, जिन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग को गंभीर चिंतन के लिए विवश कर दिया है। ऐसा नहीं है कि भारतीय इतिहास में यह पहला छात्र आंदोलन था, जिसके दबाव में सरकार को झुकना पड़ा हो। अब प्रश्न जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के संदर्भ में है। क्या यह वास्तव में केवल छात्र आंदोलन था? क्या इसका सरोकार केवल छात्रों और उनके भविष्य से था? क्या छात्रों को सरकार के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या उनकी भावनाओं और संवेदनाओं का राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है? क्या यह आंदोलन संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) की भावना के अनुरूप था? ऐसे अनेक प्रश्न हैं, जो इस पूरे प्रकरण पर गंभीर चिंतन के लिए विवश करते हैं। धरना स्थल से अनेक विरोधाभासी तस्वीरें सामने आईं। कहीं छात्रों की पिटाई के दृश्य दिखाई दिए, तो कहीं पुलिसकर्मियों पर हिंसक हमले। कहीं युवाओं को सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाते देखा गया, तो कहीं आजादी के नाम पर विवादास्पद नारे लगाए गए। कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, तो कहीं सनातन धर्म के विरुद्ध कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां सुनने को मिलीं। कुछ स्थानों पर प्रधानमंत्री के विरुद्ध अशोभनीय भाषा का प्रयोग भी देखने को मिला। ... नहीं, तो देश की मारोगे, ... मारो, बच्चों को नहीं! जैसी अमर्यादित नारों वाली तख्तियां के अलावा अश्लील इशारे तथा सैनिटरी नैपकिन लेकर प्रदर्शन करती युवतियों के दृश्य यह प्रश्न खड़ा करते हैं कि क्या वे वास्तव में छात्राएं थीं? इसी प्रकार, सड़क पर राष्ट्र प्रधान की तस्वीर बनाकर अश्लील हरकत करने वाले वीडियो भी व्यापक चर्चा का विषय बने। ऐसे दृश्य समाज के एक बड़े वर्ग को चिंतित और शर्मिंदा करते हैं। साथ ही, यह तथाकथित जेन-जी की शिक्षा, संस्कार और सामाजिक मूल्यों पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। यह देश की कैसी नई पीढ़ी तैयार हो रही है? क्या जेन-जी भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से दूर होती जा रही है? अथवा जंतर-मंतर में अन्य समूह भी सक्रिय थे। किसी भी राजनीतिक दल या उसके निर्णय का विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, किंतु किसी धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्र के विरोध में एकजुटता किसी भी स्थिति में उचित नहीं कही जा सकती।

बुधवार को करें ये विशेष उपाय कई परेशानियां होंगी दूर

भगवान गणेश स्वयं रिद्धि-सिद्धि के दाता और शुभ-लाभ के प्रदाता हैं। वे भक्तों की बाधा, संकट, रोग-दोष तथा दरिद्रता को दूर करते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि श्री गणेश जी विशेष पूजा का दिन बुधवार है। बुधवार का दिन बुध देव को समर्पित है।

श्री गणेश को सभी दुखों का पालनहार माना जाता है। गणेश जी को भौतिक, दैहिक और अध्यात्मिक कामनाओं के सिद्धि के लिए सबसे पहले पूजा जाता है। इसके अलावा यदि इस दिन भगवान गणेश की भी पूजा की जाए तो अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। प्रथम पूज्य गणेशजी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। बुधवार के दिन ये विशेष उपाय कर आप अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। गाय को पूजनीय और पवित्र माना गया है। बुधवार के दिन गाय माता को हरी घास खिलानी चाहिए। माना जाता है कि गौ माता की सेवा से सभी देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है। यदि कुंडली में बुध ग्रह के दोष हैं तो बुधवार के दिन श्री गणेश को मोदक का भोग लगाएं।

यदि आपकी कुंडली में बुध नीच स्थान में बैठा है और इस कारण आपको अनेक परेशानियों का सामना करना पड रहा है तो आप किसी ज्योतिष से डली का अध्ययन करवा कर छोटी अंगुली में पन्ना रत्न धारण करें। बुधवार के दिन गणेश जी को सिंदूर चढाने से लाभ होता है। मूंग, बुध ग्रह से संबंधित अनाज है। इसका दान करने से बुध ग्रह के दोष शांत होते हैं। अत: बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद एवं गरीब व्यक्ति को मूंग का दान करें। इसके अलावा बुध ग्रह के कुप्रभाव को कम करने के लिए बुधवार की सुबह शौच-स्नानादि से पवित्र होकर गणेश जी के मंदिर जाकर दूर्वा चढाने से लाभ होगा। दूर्वा की 11 या 21 गांठ चढाएंगें तो जल्दी ही गणेश जी की कृपा होगी। भगवान श्री गणेश को सभी दुखों का पालनहार माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रमुख पांच देवी-देवता यानी कि सूर्य, विष्णु, शिव,शक्ति और गणपति में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। क्योंकि गणेश जी को भौतिक, दैहिक और अध्यात्मिक कामनाओं के सिद्धि के लिए सबसे पहले पूजा जाता है। इसलिए इन्हें गणाध्यक्ष और मंगलमूर्ति कहा जाता हैं। इस दिन भगवान की पूजा सच्चें मन से करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में है तो इस दिन पूजा करने से वह भी शांत हो जाता है। बुधवार को गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए इन उपायों से हर समस्या का निवारण हो जाएगा।

गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर जब घर लाएं तो सबसे पहले यह ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाएं हाथ की ओर घुमी हुई हो। ऐसी मान्यता है कि दाएं हाथ की ओर मुडी हुई सूंड वाली गणेश जी प्रतिमा की पूजा से मनोकामना सिद्ध होने में देर लगती है क्योंकि इस तरह की सूंड वाले गणेश जी देर से प्रसन्न होते हैं। गणेश जी प्रतिमा में यह भी ध्यान रखें कि गणेश जी सायुज और सवाहन हों। यानी गणेश जी के हाथों में उनका एक दंत, अंकुश और मोदक होना चाहिए। गणेश जी एक हाथ वरदान की मुद्रा में हो और साथ में उनका वाहन मूषक भी होना चाहिए। शास्त्रों में देवताओं का आवाहन इसी रुप में होता है।जो लोग संतान सुख की कामना रखते हैं उन्हें अपने घर में बाल गणेश की प्रतिमा या तस्वीर लानी चाहिए। नियमित इनकी पूजा से संतान के मामले में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर होती है। घर में आनंद उत्साह और उन्नति के लिए नृत्य मुद्रा वाली गणेश जी की प्रतिमा लानी चाहिए। इस प्रतिमा की पूजा से छात्रों और कला जगत से जुडे लोगों को विशेष लाभ मिलता है। इससे घर में धन और आनंद की भी वृद्धि होती है। गणेश जी आसान पर विराजमान हों या लेटे हुए मुद्रा में हों तो ऐसी प्रतिमा को घर में लाना शुभ होता है। इससे घर में सुख और आनंद का स्थायित्व बना रहता है। सिंदूरी रंग वाले गणेश को समृद्धि दायक माना गया है, इसलिए इनकी पूजा गृहस्थों एवं व्यवसायियों के लिए शुभ माना गया है। वास्तु विज्ञान के अनुसार गणेश जी को घर के ब्रहम स्थान (केंद्र) में, पूर्व दिशा में एवं ईशान में विराजमान करना शुभ एवं मंगलकारी होता है इस बात का ध्यान रखें कि घर में जहां भी गणेश जी को विराजमान कर रहे हों वहां कोई और गणेश जी की प्रतिमा नहीं हो। अगर आमने सामने गणेश जी प्रतिमा होगी तो यह मंगलकारी होने की बजाय आपके लिए नुकसानदेय हो जाएगी।

वास्तुशास्त्र

सुख शांति चाहते हैं तो घर में ऐसी सजावट न करें

वास्तु विज्ञान में जमीन की बनावट, घर की दिशा एवं घर में रखी चीजों का आंकलन किया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की जमीन, घर की दिशा, मुख्य द्वार एवं घर में रखी हुई चीजें भी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालती हैं। इसलिए घर में ऐसी चीजों को ही रखना चाहिए जिससे सकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो। वास्तु विज्ञान में कहा गया है कि युद्ध से संबंधित चीजें जैसे, तलवार, बंदूक आदि नहीं रखना चाहिए। इससे क्रोध एवं आपस में द्वेष बढ़ता है।

बहुत से लोग घर में महाभारत की तस्वीर लगाते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार यह भी घर की सुख-शांति में बाधक होता है। महाभारत एक पारिवारिक युद्ध था जो परिवार में संघर्ष की भावना को बढ़ाता है। इसलिए महाभारत की तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए।

शिव की नटराज मूर्ति भी लोगों को काफी पसंद आता है। ड्राईंग रूम इसे लोग बड़े शौक से रखते हैं खास तौर पर कला से जुड़े लोगों इसे श्रद्धापूर्वक घर में रखते हैं। जबकि वास्तु के अनुसार शिव की नटराज मूर्ति विनाश का प्रतीक है क्योंकि जब शिव क्रोधित होते हैं तो नृत्य करते हैं। शिव के ताण्डव नृत्य से प्रलय मच जाता है। इसलिए घर में शिव की नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति अथवा तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। ?

अठारह पुराणों में गरूड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें प्रेत क्रिया। मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति और गति का वर्णन मिलता है। इस पुराण का पाठ किसी की मृत्यु के पश्चात आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए।

टाईटेनिक के पॉपुलर के होने के बाद से बहुत से लोग टाईटेनिक की तस्वीर घर में लगाने लगे हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार डूबते नाव की तस्वीर घर में नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। इससे घर के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल में कमी आती है।

ताजमहल की तस्वीर और शो पीस से घर को सजाना बहुत से लोगों को पसंद आता है। जबकि ताजमहल एक समाधि है जो मौत की निशानी और नकारात्मकता का प्रतीक है। इसे प्रेम का प्रतीक मानकर घर में नहीं रखना चाहिए। इससे पति-पत्नी के बीच प्रेम बढ़ने की बजाय दूरी बढ़ने का ख्याल बार-बार आता है।

क्या करें कि हम अच्छी जिंदगी जी पाएं...

चित्त को शांत व स्थिर करने के लिए हमें सबसे पहले अपने रोजमर्रा के जीवन से तनाव निकाल फेंकना होगा। इसके लिए क्या-क्या करें हम।

आप भीड भरे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आपका पारा धीरे-धीरे चढता जा रहा है। कोई आपसे गाडी आगे निकालने की कोशिश करता है और आप उबल पडते हैं। आप हॉर्न बजाते हैं, कोसते हैं, झुंझलाते हैं। इस तरह आप बडे बुरे मूड में ऑफिस काम पर पहुंचते हैं।

आप जरूरी कागज तलाशते हैं और वह आपको नहीं मिलता, आपकी डेस्क पर सारी चीजें अस्त- व्यस्त पडी होती हैं। आपकी मेल का इनबॉक्स भी बहुत बुरी हालत में है और आपको 25 मेल के उत्तर देने हैं। आप पहले ही कई असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स में देरी कर चुके हैं और बॉस आपसे खुश नहीं हैं। 11 बजने से पहले आपको बहुत जरूरी 3 काम पूरे करने थे और 12 बज चुके हैं।

रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। यह तो सिर्फ एक बानगी है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हो सकता है कि आपका रोजमर्रा का जीवन इतना बुरा न हो, लेकिन इससे आपको उन बातों का पता तो चल ही गया होगा, जिनके कारण लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं। यदि आप कोशिश करें, तो तनाव को दूर कर सकते हैं और अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। तनाव की पहचान करना पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इससे दूर करने के उपाय की तलाश करना आसान हो जाएगा। स्वयं को दस मिनट दें और सोचें कि आज आप तनाव में क्यों रहे। सप्ताह में ऐसा कितनी बार होता है। टॉप 10 की एक लिस्ट बनाएं और देखें कि क्या आप उनमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं या नही। एक-एक करके उन्हें सुधारते जाएं। अनावश्यक संकल्पों को छोड दें। संकल्प पूरा करने का दबाव अच्छे परिणाम की अपेक्षा तनावग्रस्त करता है। उस संकल्प को पहले दूर करें, जो ज्यादा तनाव देता हो।

टालमटोल की प्रवृत्ति तो हर कीमत पर छोडने ही होगी। स्वयं को व्यवस्थित करना बेहद जरूरी है। अव्यवस्था से तनाव बढता है। शुरुआत अपनी टेबल और दराज से की जा सकती है। घर के किसी एक कोने से शुरुआत करें। सहज और सरल दिनचर्या कई समस्याओं को स्वयंमेव समाप्त कर देती है। जल्दी उठें। देर से उठना कई परेशानियों की जड है। जल्दी उठने और जल्दी सोने की आदत से ट्रैफिक और ड्राइविंग की समस्या के साथ-साथ और भी कई समस्याओं से निजात पा सकते हैं। एक छोटे-से अंतराल से बडा बदलाव आ सकता है।

सिर्फ दस मिनट का परिवर्तन लाकर देखें। आपको फर्क पता चल जाएगा। दूसरों को नियंत्रित न करें। याद रखें, हम सारी दुनिया के मालिक नहीं हैं। हम चीजों और लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और इसमें सफल नहीं हो पाते। इससे तनाव बढता है।

स्वयं पर नियंत्रण रखा जा सकता है, लेकिन दूसरों पर नहीं। स्वयं पर काम थोपने की बजाय उसे दूसरों से भी कराया जा सकता है। दूसरों को अधीन रखने की अदम्य इच्छा को हमेशा के लिए त्याग दें। मुश्किल लोगों से दूर रहें। कभी-कभी कुलीग, कस्टमर, पडोसी आदि हमारी जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं। उनसे लडने की बजाय उनकी बातों को निर्विकार भाव से सुनकर टालने में ही भलाई है। सबसे बडी बात तो ऊर्जा के क्षय को हमें रोकना चाहिए। रोजमर्रा के जीवन में इंसान कई ऐसे काम करता है, जिसमें सिर्फ ऊर्जा का क्षय होता है। जिस काम का कोई मतलब न हो जैसे कि क्रोध करना, दूसरों से ईर्ष्या करना आदि को पहचानें और उसे हटा दें। जिंदगी बेहतर जीने के लिए भरपूर ऊर्जा होना जरूरी है।

पुराणों में संस्मरण है कि एक बार मां पार्वती ने बडी उत्सुकता के साथ बाबा श्री विश्वनाथ देवाधिदेव महादेव से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यूं होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षो की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है।

क्यों जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता, वह अमर हो जाता है

जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यूं मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यूं और आपके अमर होने का कारण व रहस्य क्या है।

जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यूं। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यूं। और आपके कंठ में पडी यह परमुण्ड माता तथा आपके अमर होने का कारण व रहस्य क्या है। महाकाल ने पहले तो माता को यह गूढ रहस्य बताना उचित नहीं समझा परन्तु माता की स्त्री हठ के आगे उनकी एक न चली। तब अन्त्वोगत्व्या महादेव शिव को मां पार्वती को अपनी साधना की अमर कथा, जिसे हम अमरत्व की कथा के रूप में जानते हैं, इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में कही। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी से एकान्त व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई भी जीव, व्यक्ति और यहां तक कोई पशु-पक्षी न सुन लें, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता, वह अमर हो जाता। इस कारण शिव जी मां पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पडे। सबसे पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड दिया, इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का तात्पर्य या बोध होता है।

आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं में चन्द्रमा को चंदनवाडी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पो को शेषनाग पर छोड दिया। इस प्रकार इस पडाव का नाम शेषनाग पडा। आगे की यात्रा में अगला पडाव गणेश टाप पडता है, इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीडे को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके साथ मां पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश कर अमर कथा को न सुने, इसलिए शिव जी ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रवलित कर दी। फिर शिव जी ने जीवन की अमर कथा मां पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते-सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। इस समय दो सफेद कबूतर श्री शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच-बीच में गूं-गूं की आवाज निकाल रहे थे, शिव जी को लग रहा था कि मां पार्वती कथा सुन रही है और बीच-बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती मां की ओर गया जो सो रही थी। शिव जी ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही है, तब इसे सुन कौन रहा था। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पडी। महादेव शिव कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड दिया और उन्हें आर्शीवाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अत: यह कबूतर का जोडा अजय अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहां प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा पडा। जहां गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फके निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पवित्र गुफा में मां पार्वती के अलावा गणेश के भी अलग से बर्फसे निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में भी एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक गडरिये को एक साधू मिला, जिसने उस गडरिये को कोयले से भरी एक बोरी दी जिसे गडरिया अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया।

घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्कों की हो चुकी थी। इसके बाद वह गडरिया साधू से मिलने व धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया जहां पर साधू से मिला था।

सभी कष्ट दूर करे श्री हनुमान उपासना

भगवान रामभक्त हनुमान की उपासना से जीवन के सारे कष्ट, संकट मिट जाते हैं। माना जाता है कि हनुमान ऐसे देव हैं जो थोड़ी-सी प्रार्थना और पूजा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं।

जहां मंगलवार और शनिवार का दिन इनके पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं वहीं हिन्दू पंचांग के अनुसार पौष कृष्ण अष्टमी को हनुमान पूजन विशेष मायने रखता है।

अगर आप अपनी परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो आप निम्न मंत्र और उपाय आजमाएं।

शीघ्र ही आपके कष्ट दूर होकर आपको सुख की अनुभूति होगी।

- ऊं हं हनुमंतये नम: मंत्र का जप करें।
- ऊं हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट् का रुद्राक्ष की माला से जप करें।
- संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा।
- राम-राम नाम मंत्र का 108 बार जप करें।
- हनुमान को नारियल, धूप, दीप, सिंदूर अर्पित ? करें।
- हनुमान अष्टमी के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।
- राम रक्षा स्त्रोत, बजरंगबाण, हनुमान अष्टक का पाठ करें।
- हनुमान आरती, हनुमत स्तवन, राम वन्दना, राम स्तुति, संकटमोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें।
- परिवार सहित मंदिर में जाकर मंगलकारी सुंदरकांड पाठ करें।
- हनुमान को चमेली का तेल, सिंदूर का चोला चढ़ाएं।
- गुड-चने और आटे से निर्मित प्रसाद वितरित करें।

आषाढ मास क्यों है एक महत्वपूर्ण मास, इससे समस्त पाप हो जाते हैं नष्ट

इस माह का धार्मिक महात्म्य बहुत ही विशेष है। इस माह में किया गया दान-पुण्य मनुष्य के लिए पुण्य फलदायक रहता है। आषाढ मास एक महत्वपूर्ण मास हैं । आइए जानें, इसके बारे में खास जानकारियां । आषाढ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस दिन लोग पूरे दिन का व्रत रखकर भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान कराकर भोग लगाते हुए पुष्प, धूप, दीप से आरती करते हैं। गरीब ब्राहमणों को दान भी किया जाता है। इस एकादशी के बारे में मान्यता है कि मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है । आषाढ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को 'गुरु पूर्णिमा' अथवा 'व्यास पूर्णिमा' कहते हैं। इस दिन लोग अपने गुरु के पास जाते हैं तथा उच्चासन पर बैठाकर माल्यापर्ण करते हैं तथा पुष्प ,फल, वस्त्र आदि गुरु को अर्पित करते हैं। यह गुरु - पूजन का दिन होता है जिसकी प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है।

आषाढ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को व्रत किया जाता है। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली एवं संपूर्ण पापों का हरण करने वाली है। इसी एकादशी से चातुर्मास्य व्रत भी प्रारंभ होता है। इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैय्या पर तब तक शयन करते हैं, जब तक कार्तिक शुक्ल मास की एकादशी नहीं आ जाती है। अत: आषाढ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण भी अवश्य करना चाहिए। विष्णु एकादशी के दिन से देवी-देवता चार माह के लिए शयन करने चले जाएँगे। इसे चातुर्मास भी कहा जाता है। देवी-देवताओं के चार माह तक विश्राम में जाने की अवधि तक शास्त्रों के मुताबिक सभी मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। चार माह बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवता शयन से उठेंगे, जिसे देवउठान एकादशी कहा जाता है। देवउठान एकादशी के बाद फिर से विवाह लग्न प्रारंभ हो जाएँगे।

मांगलिक कार्य रहेंगे वर्जित

हिन्दू पंचांग के अनुसार चैत्र माह से प्रारंभ होने वाले वर्ष के चौथे माह यानी आषाढ मास को वर्षा ऋतु का महीना भी कहा जाता है। आषाढ को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार इन महीनों में शुभ विवाह के मांगलिक कार्य नहीं होंगे।

इस बार गुरु-शुक्र के उदय व अस्त होने से अच्छी बारिश होने के भी आसार हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवता शयन से उठेंगे जिसे 'देवउठनी एकादशी' कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के बाद फिर से विवाह लग्न प्रारंभ हो जाएंगे। आषाढ मास में भगवान विष्णु का प्रिय पुरुषोत्तम मास भी है अत: इस माह का धार्मिक महात्म्य बहुत ही विशेष है। इस माह में किया गया दान-पुण्य मनुष्य के लिए पुण्य फलदायक रहता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर रुका!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिली है. यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. मामले में 28 जुलाई को मुरादाबाद कमिश्नर कार्यालय में सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन शोक अवकाश के कारण हड़ताल रहने से सुनवाई नहीं हो सकी. इसके बाद यूनिवर्सिटी की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने अंतरिम राहत देते हुए ध्वस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी. इस आदेश के बाद फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर बुलडोजर कार्रवाई टल गई है. इससे पहले रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा मुलाकात के लिए जेल पहुंचीं. उनके साथ उनके बड़े बेटे अदीब आजम और सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर मौजूद रहे।

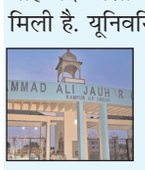

ब्लैक सी में भारतीय नाविक की मौत पर भारत सख्त

नईदिल्ली। ब्लैक सी में कॉमर्शियल जहाज पर हुए हमले में भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया है. विदेश मंत्रालय ने सोमवार को भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉ. ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया और घटना को लेकर गंभीर चिंता जताई. यह मामला कॉमर्शियल जहाज रूक्ष्क्ष्क्ष्क्षद्ध पर हुए हमले से जुड़ा है, जिसमें एक भारतीय नागरिक की जान चली गई थी. विदेश मंत्रालय ने यूक्रेनी राजदूत के सामने कमर्शियल जहाजों पर इस तरह के हमलों की कड़ी निंदा की. मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं का समुद्री सुरक्षा, स्वतंत्र नौवहन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर गंभीर असर पड़ता है. विदेश मंत्रालय ने यूक्रेनी राजदूत से कहा कि वह भारत की चिंताओं से यूक्रेन के अधिकारियों को अवगत कराएं. भारत ने साफ किया कि कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने वाली ऐसी कार्रवाई निर्दोष नागरिक नाविकों की जिंदगी को खतरे में डालती हैं और इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।

दुबई से मुंबई आ रही इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

नईदिल्ली। दुबई से मुंबई आ रही इंडिगो की एक इंटरनेशनल फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. हवा में उड़ान के दौरान ही पायलट को विमान के एक हिस्से से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और नजदीकी राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधा.इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6श्व1452 (फ्लाइट टाइप₹321) दुबई से मुंबई के लिए उड़ान पर थी. यात्रा के दौरान दोपहर करीब 2ः45 बजे फ्लाइट के कार्गो होल्ड एरिया में धुआं महसूस हुआ. ऐसे में पायलट को मे डे कॉल दिया था. खतरे का अंदेशा होते ही राजकोट एयरपोर्ट पर दोपहर 2ः45 बजे %फुल इमरजेंसी% घोषित कर दी गई. आपात स्थिति को देखते हुए तुरंत अलर्ट जारी किया गया और रनवे के आसपास पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को स्टैंडबाय पर तैनात कर दिया गया।

मुसलमान दरी नहीं बिछाएंगे, बराबरी का हक मांगेंगे:ओवैसी

लखनऊ। यूपी के मुरादाबाद में आयोजित एक जनसभा के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदेश के मुसलमानों से अपनी राजनीतिक लीडरशिप तैयार करने और आने वाले विधानसभा चुनावों में हिस्सेदारी तय करने का आह्वान किया. ओवैसी ने कहा कि अब मुसलमान केवल वोट बैंक बनकर दरी नहीं बिछाएंगे, बल्कि बराबरी का हक मांगेंगे. उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर वह कुर्सी पर बैठेंगे तो ओवैसी भी सामने कुर्सी पर पैर से पैर मिलाकर बैठकर हक और इंसाफ की बात करेगा. जनसभा में उन्होंने भाजपा को हराने के लिए चुनाव से पहले गठबंधन करने की भी पेशकश की. उन्होंने मुरादाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज, एमआरआई जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और स्मार्ट सिटी परियोजना के विकास कार्यों में बरती जा रही कमियों पर सवाल उठाए. अपने संबोधन के अंत में ओवैसी ने विपक्ष को खुला संदेश दिया।

ताहिर हुसैन की सजा पर 31 जुलाई को फैसला

नईदिल्ली। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में 31 जुलाई को ताहिर हुसैन और अन्य को अदालत 31 जुलाई को फैसला सुनाएगी. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन और उनके सह-दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी. पुलिस ने सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि अपराधियों ने बेहद क्रूर और जघन्य तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है जो इन लोगों की सोची-समझी साजिश थी. अंकित शर्मा के शरीर पर हमलावरों ने 51 गंभीर चोटों के निशान मिले थे. कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि इस तरह के बर्बर और अक्षम्य अपराध के लिए सभी दोषियों को केवल मौत की सजा के हकदार हैं.दिल्ली पुलिस ने सजा पर बहस करते हुए कोर्ट में कहा कि वारदात के वक्त आरोपी कसाई बन चुके थे. पुलिस ने इस हत्या को ठंडे दिमाग से की गई हत्याबताया और कहा कि अपराध करते समय आरोपी कसाई और जानवर बन गए थे. साथ ही पुलिस ने दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए इस हत्याकांड को घिनौना और बेहद बेरहम था।

देहरादून में पुल धंसने से यातायात बाधित

उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण चारधाम यात्रा स्थगित

देहरादून। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मंगलवार को चारधाम यात्रा दो दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वहीं, देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में टोंस नदी पर बने पुल का संपर्क मार्ग धंसने से करीब 12 घंटे तक यातायात बाधित रहा।

प्रदेश में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण दो राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गईं। खराब मौसम और विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर देहरादून, चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में कक्षा एक से 12 तक के स्कूल बंद रखे गए। मौसम विभाग द्वारा अधिकांश जिलों के लिए जारी 'ऑरेंज अलर्ट' के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को चौबीसों घंटे सतर्क रहने, बंद मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने तथा आपात स्थिति के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए।

गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि यात्रा मार्गों के कई स्थानों पर भूस्खलन और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर मंगलवार और बुधवार के लिए चारधाम यात्रा स्थगित की गई। उन्होंने बताया कि मौसम अनुकूल होने पर यात्रा फिर शुरू की जाएगी। प्रेमनगर क्षेत्र के नंदा की चौकी में तड़के हुई मूसलाधार बारिश के कारण टोंस नदी पर बने पुल का संपर्क मार्ग धंस गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया।

अधिकारियों ने बताया कि पुल का मुख्य ढांचा सुरक्षित है लेकिन लगातार बारिश से संपर्क मार्ग के नीचे की मिट्टी बह जाने के कारण उसका एक हिस्सा धंस गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त रूप से मरम्मत कार्य किया तथा करीब 12 घंटे में संपर्क मार्ग को दुरुस्त कर यातायात बहाल कर दिया गया। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि टोंस नदी के तेज बहाव को देखते हुए उसके प्रवाह की दिशा नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।

पूर्वी हिस्से में पशुधन को बचाना बड़ी चुनौती सरकार और संगठन कर रहे मदद

गुवाहाटी। भीषण बाढ़ से जूझ रहे पूर्वी असम में पशुधन की सुरक्षा एक प्रमुख चुनौती बनकर उभरी है, क्योंकि प्रभावित परिवारों की बड़ी संख्या अपनी आजीविका के लिए मवेशियों और मुर्गियों पर निर्भर है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य सरकार जानवरों के लिए चारा और चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करा रही है।

निजी संगठन भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। राज्य की पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री नीलिमा देवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ''बाढ़ के इस मुश्किल समय में अपने पशुधन की सुरक्षा करना भी उतना ही ज़रूरी है।'' उन्होंने कहा कि शिवसागर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उनका विभाग चारा और पशु चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करा रहा है, ताकि पालतू जानवरों को बचाया जा सके। देवी ने कहा, ''सरकार संकट की इस घड़ी में हर जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।'' मंत्री ने संकट की इस घड़ी में मदद करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों का भी धन्यवाद किया।

उन्होंने कहा, ''...'अहिंसा हेल्पिंग हैंड्स फॉर पॉज़ फाउंडेशन' और परवाह के चंदमिता दास, अभय बोरा एवं उनके साथी स्वयंसेवकों को शिवसागर में कई स्थानों पर उनकी निस्स्वार्थ सेवा के लिए हार्दिक धन्यवाद।'' देवी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में गायों, कुत्तों, बिल्लियों, सूअरों, बकरियों और अन्य जानवरों को चारा एवं दवाइयां उपलब्ध कराना वाकई काबिल-ए-तारीफ और प्रेरणादायक है।

उन्होंने मुख्य अभियंता को घटना की प्राथमिक जांच कर तीन दिन में रिपोर्ट सौंपने और जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। पांडेय ने कहा कि जांच में किसी अधिकारी या ठेकेदार की लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले वर्ष सितंबर में प्राकृतिक आपदा के दौरान यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया था इसके बाद निकट ही अस्थायी पैंटून पुल बनाया गया था, जो इस महीने 12 जुलाई को भारी बारिश में बह गया। इसके बाद मरम्मत किए गए मूल पुल को यातायात के लिए खोला गया था। इस बीच, कांग्रेस ने पुल की मरम्मत की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।

कांग्रेस ने कार्यों की गुणवत्ता को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार ने प्रदेश की जड़ें खोखली कर दी हैं, जहां 16 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत किया गया पुल 16 दिन भी नहीं टिक सका। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने लोक निर्माण मंत्री को बर्खास्त करने और पुल की मरम्मत की निगरानी करने वाले अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की।

असम में बाढ़ का कहर

प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों के साथ की समीक्षा बैठक

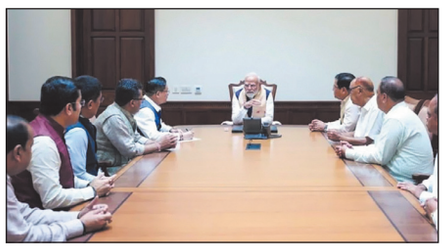

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने असम के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त बाढ़ की स्थिति पर राज्य के सांसदों के साथ बैठक की। इसके साथ ही आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है।

एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लोगों की सुरक्षा और कुशलक्षेम के लिए प्रार्थना की। उन्होंने एक्स पर लिखा, असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। मैं सभी की सुरक्षा और कुशल मंगल की कामना करता हूं।

बैठक में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने भाग लिया। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के अनुसार, बाढ़ से छह जिलों - शिवसागर, गोलाघाट, चराइदेव, जोरहाट, नागांव और कामरूप (महानगर) में 4,45,495 लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से कुल 90 राहत कैंप चल रहे हैं, जिनमें 28,695 लोगों को आश्रय दिया गया है। इसके अलावा, राहत सामग्री बांटने वाले 94 केंद्र भी काम कर रहे थे।

इस बीच, असम के शिवसागर जिले में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है क्योंकि नौजान गांव में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया और सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे सैकड़ों परिवार आश्रय, भोजन और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि राहत अभियान तेज कर दिए गए हैं।

वहीं, असम के विधायकों ने एक बड़ा फैसला लिया है। रायजोर दल को छोड़कर सभी विधायकों ने मंगलवार को राज्य के बाढ़ पीड़ितों की राहत और पुनर्वास के लिए अपने एक महीने का वेतन दान करने की घोषणा की।

अध्यक्ष रणजीत कुमार दास ने कहा कि वह और उपाध्यक्ष हब्बे टेरोन बाढ़ राहत के लिए एक महीने का वेतन दान करेंगे। उन्होंने घोषणा की, हमारे अलावा, विधानसभा सचिवालय के सभी कर्मचारी पीड़ितों की राहत और पुनर्वास के लिए एक दिन का वेतन दान करेंगे।

इस पहल का स्वागत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि भाजपा के सभी विधायक भी एक महीने का वेतन दान करेंगे। राज्य में तृणमूल कांग्रेस के इकलौते विधायक शेरमन अली अहमद ने भी ऐसा ही किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए अपने एक महीने का वेतन दान करने की घोषणा की।

भारतीय वायुसेना की ओर से असम और नागालैंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियान लगातार जारी है। खराब मौसम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद वायुसेना राहत एवं बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से जुटी हुई है। मंगलवार को भारतीय वायुसेना ने बताया कि पिछले 10 दिनों के दौरान उसके हेलीकॉप्टरों ने बाढ़ में फंसे 458 लोगों को सुरक्षित बचाकर निकाला है।

वायु सेना के मुताबिक, अभी तक प्रभावित क्षेत्रों में हवाई मार्ग से 9 टन से अधिक आवश्यक राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है। वायुसेना के अधिकारी व जवान, राहत अभियान के दौरान हेलीकॉप्टर से लगातार दुर्गम और जलमग्न क्षेत्रों में उड़ान भर रहे हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का एलान

नई दिल्ली। अगस्त में श्रीलंका में होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के लिए भारत की टीम में अनकैप्ड ऑफ-स्पिनिंग ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है। सारांश को वॉशिंगटन सुंदर की हैमस्ट्रिंग चोट के कारण चुना गया है। सुंदर को आधिकारिक तौर पर पहले टेस्ट से बाहर कर दिया गया है। घरेलू क्रिकेट और इंडिया ए के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद, 33 साल की उम्र में सारांश को टेस्ट कैप मिल सकती है। जून में अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में आराम दिए जाने के बाद ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की भी टीम में वापसी हुई है। पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक सुबह 10:00 बजे से गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक सुबह 10:00 बजे से कोलंबो (एसएससी) में होगा।

15 खिलाड़ियों की बाकी टीम जानी-पहचानी लग रही है, जिसमें जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालेंगे। हालांकि, बुमराह और मौजूदा नंबर 3 बल्लेबाज साई सुदर्शन को फिटनेस क्लीयरेंस मिलने की शर्त पर चुना गया है, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी, जो इस समय ष्टश्वश्च में रिहैब कर रहे कई खिलाड़ियों में से एक हैं टीम का हिस्सा नहीं हैं।

अनुभवी रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका में होने वाली दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए मंगलवार को भारतीय टीम में वापसी की जबकि ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और शीर्ष क्रम के बल्लेबाज बी साई सुदर्शन को भी 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है।

भारतीय टीम : शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 70 अंक टूटा निफ्टी 23,985 पर बंद

नईदिल्ली। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार पूरे कारोबारी सत्र के दौरान सीमित दायरे में कारोबार करता रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी 50 मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार पर पीएसयू बैंक, एफएमसीजी और केमिकल सेक्टर के शेयरों का दबाव देखने को मिला, जबकि आईटी सेक्टर ने शानदार प्रदर्शन किया। सेंसेक्स 69.86 अंक यानी 0.09 फीसदी की गिरावट के साथ 76,765.92 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 10.60 अंक यानी 0.04 फीसदी फिसलकर 23,985.35 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 50 में हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और कोल इंडिया सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में शामिल रहे। व्यापक बाजार में मिला-जुला रुख देखने को मिला। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.08 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ।

एचयूएल का पहली तिमाही का शुद्ध लाभ 3.17 प्रतिशत घटा

नई दिल्ली। दैनिक उपभोग का सामान बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) का चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 3.17 प्रतिशत घटकर 2,680 करोड़ रुपए रह गया। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 2,768 करोड़ रुपए था। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उत्पादों की बिक्री से राजस्व 10.26 प्रतिशत बढ़कर 17,149 करोड़ रुपए हो गया, जो एक वर्ष पहले की समान तिमाही में 15,552 करोड़ रुपए था। एचयूएल ने अपने आय विवरण में कहा कि यह पिछले 13 तिमाहियों की सर्वाधिक वृद्धि है। इस दौरान अंडरलाइंग सेल्स ग्रोथ (यूएसजी) 10 प्रतिशत रही।

एप्पल फिर बना दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी

नईदिल्ली। एप्पल ने एक बार फिर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी का ताज हासिल कर लिया है। सोमवार को कंपनी के शेयरों में करीब 1% की बढ़त दर्ज हुई, जिससे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 4.95 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया। इसके साथ ही एप्पल ने एआई चिप निर्माता एनविडिया को पीछे छोड़ दिया। वहीं, एनविडिया के शेयरों में करीब 5% की गिरावट आई, जिसके बाद कंपनी का मार्केट कैप लगभग 4.77 ट्रिलियन डॉलर रह गया। दोनों कंपनियों के बीच पिछले कुछ समय से वैल्यूएशन को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। एनविडिया पर दबाव उस रिपोर्ट के बाद बढ़ा, जिसमें कहा गया कि कंपनी ओपन एआई के ओहियो डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए करीब 250 बिलियन डॉलर की वित्तीय गारंटी देने पर बातचीत कर रही है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

अशोक लेलैंड ने यूको बैंक से साझेदारी की

नई दिल्ली। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड ने अपने ट्रक और बसों के खरीदारों को वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यूको बैंक के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत अशोक लेलैंड और यूको बैंक, अशोक लेलैंड के ट्रक तथा बस खरीदने वाले ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुरूप वित्तीय समाधान उपलब्ध कराएंगे। अशोक लेलैंड के पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के. एम. बालाजी ने कहा, यह रणनीतिक साझेदारी हमारे वाणिज्यिक वाहनों की श्रृंखला को देशभर के कारोबारों के लिए अधिक सुलभ बनाकर बाजार में हमारी मौजूदगी को और मजबूत करेगी।

मीराबाई ने रचा इतिहास, खेल महाशक्ति बनने की दस्तक

कुमार कृष्णन

खेलों के इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो केवल पदकों की संख्या से नहीं, बल्कि अपने सांकेतिक महत्व से याद रखे जाते हैं। वे किसी खिलाड़ी की व्यक्तिगत उपलब्धि से आगे बढ़कर पूरे राष्ट्र के आत्मविश्वास, उसकी सामूहिक आकांक्षाओं और भविष्य की दिशा का संकेत बन जाते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू का स्वर्ण पदक ऐसा ही एक क्षण है। महिलाओं की 48 किलोग्राम स्पर्धा में 190 किलोग्राम भार उठाकर उन्होंने केवल स्वर्ण पदक ही नहीं जीता, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि भारतीय खेल अब प्रतिभा के भरोसे नहीं, बल्कि निरंतरता, वैज्ञानिक तैयारी और अदम्य आत्मविश्वास के नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं।

ग्लासगो में भारत के अभियान की शुरुआत जिस अंदाज़ में हुई, उसने यह संदेश दिया कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत अब केवल पदक तालिका में सम्मानजनक स्थान पाने का लक्ष्य लेकर नहीं उतरता, बल्कि अनेक स्पर्धाओं में प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता विकसित कर चुका है। भारोत्तोलन में पहले ही दिन स्वर्ण और दो रजत पदक इस विश्वास को और मजबूत करते हैं।

मीराबाई चानू ने स्नैच में 85 किलोग्राम तथा क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम भार उठाकर कुल 190 किलोग्राम का स्कोर बनाया। यह केवल स्वर्ण जीतने के लिए पर्याप्त नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से पूरे 22 किलोग्राम अधिक वजन उठाकर अपनी श्रेष्ठता निर्विवाद रूप से स्थापित कर दी। खेलों की दुनिया में ऐसी जीतें बहुत कम देखने को मिलती हैं, जहां विजेता और दूसरे स्थान के बीच इतना बड़ा अंतर हो। यह अंतर केवल ताकत का नहीं, बल्कि तैयारी, तकनीक और मानसिक दृढ़ता का भी होता है।

इस स्वर्ण के साथ मीराबाई ने राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतकर एक नई मिसाल कायम की। किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बार चैंपियन बनना कठिन होता है, लेकिन वर्षों तक अपने प्रदर्शन को उसी स्तर पर बनाए रखना उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। खेल इतिहास बताता है कि महान खिलाड़ी वही कहलाते हैं जो समय के साथ स्वयं को बार-बार साबित करते हैं। मीराबाई अब उसी श्रेणी में खड़ी दिखाई देती हैं।

ग्लासगो में भारत की सफलता केवल मीराबाई तक सीमित नहीं रही। पुरुषों की 60 किलोग्राम स्पर्धा में चनामबम ऋषिकांत सिंह ने रजत पदक जीतकर भारतीय अभियान को नई ऊर्जा दी। उन्होंने कुल 264 किलोग्राम वजन उठाया और स्नैच में 121 किलोग्राम का भार उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड स्थापित किया। यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रिकॉर्ड केवल जीत का प्रमाण नहीं होते, वे यह बताते हैं कि खिलाड़ी प्रतियोगिता के मानकों को बदलने की क्षमता रखता है।

ऋषिकांत सिंह का प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि भारतीय भारोत्तोलन में प्रतिभाओं की नई पीढ़ी तैयार हो चुकी है। अब भारत की सफलता किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रही। यह एक स्वस्थ खेल संस्कृति की पहचान है, जहां लगातार नए खिलाड़ी सामने आते हैं और अनुभवी खिलाड़ियों की विरासत को आगे बढ़ाते हैं।

इसी क्रम में राजा मुथुपंडी ने पुरुषों की 65 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत के खाते में एक और सफलता जोड़ दी। तीन पदकों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारोत्तोलन अब भारत के लिए सबसे भरोसेमंद खेलों में शामिल हो चुका है। ग्लासगो 2026 की यह शुरुआत भारतीय खेल इतिहास में केवल पदकों के लिए याद नहीं रखी जाएगी। इसे उस क्षण के रूप में भी याद किया जाएगा, जब भारत ने दुनिया से यह कहना शुरू किया कि वह खेलों में अब संभावनाओं का नहीं, उपलब्धियों का देश है। मीराबाई चानू की स्वर्णिम मुस्कान और भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण है कि भारत खेल महाशक्ति बनने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में हुए शामिल

मील का पत्थर साबित होगा स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के समापन सत्र में शामिल हुए। उन्होंने राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित कॉन्क्लेव में विगत मार्च-अप्रैल में छत्तीसगढ़ में हुए देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में राज्य के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की। छत्तीसगढ़ में पहली बार इस स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न सत्रों में देशभर से आए खेल प्रशासकों, नीति निर्माताओं, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट्स, नामचीन खिलाड़ियों, विशेषज्ञों और खेल संघों के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाओं, खेल प्रतिभाओं की खोज, प्रशिक्षण और सुदृढ़ खेल अधोसंरचना के रोडमैप पर दिनभर मंथन किया।

मुख्यमंत्री श्रीविष्णु देव साय ने कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि विशेषज्ञों के बीच आज दिनभर हुए गंभीर विचार-विमर्श से राज्य में खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी के कार्यों को सार्थक एवं प्रभावी दिशा मिलेगी। राज्य में खेलों के विकास के लिए यह कॉन्क्लेव मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने छत्तीसगढ़ में गंभीरता से काम हो रहे हैं। उत्कृष्ट खेल मिशन के अंतर्गत खेल अधोसंरचना को मजबूत करने इस साल के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमने हाल ही में प्रदेशभर के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची को मंजूरी दी है, जिन्हें आगे जाकर सरकार नौकरी में लाभ देगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि खिलाड़ियों को खेलने के लिए अच्छा मंच उपलब्ध कराने बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के आयोजन राज्य में हुए हैं। बस्तर ओलंपिक में करीब चार लाख और सरगुजा ओलंपिक में लगभग साढ़े तीन लाख खिलाड़ियों ने भागीदारी की है। राज्य की खेल प्रतिभाओं को उचित अवसर और संसाधन देने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग सक्रियता से काम कर रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव कहा कि यह कॉन्क्लेव छत्तीसगढ़ को खेलों के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में बहुत मददगार होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियों में प्राकृतिक, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत युवा निकलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं से ही बच्चों की खेल प्रतिभा को पहचान कर उन्हें तराशने और संवारने की कार्ययोजना पर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज विशेषज्ञों के जो अमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन प्राप्त हुए हैं, उन पर निश्चित रूप से अमल किया जाएगा। आज के निष्कर्षों को शामिल कर हम विस्तृत कार्ययोजना बनाएंगे और उसे प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करेंगे।खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, संचालक मती तनुजा सलाम, ओलंपियन जिन्सन जॉनसन, प्रख्यात शिक्षाविद एवं खेल वैज्ञानिक डॉ. रत्नेश सिंह, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव विक्रम सिसोदिया, हाई परफॉर्मेंस एनॉलिस्ट रोनक कोठारी, पीईएफआई के राष्ट्रीय सचिव डॉ. पियूष जैन, खेलो इंडिया के उप महानिदेशक मयंक वास्तव और पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान सहित प्रदेश के अनेक खिलाड़ी, प्रशिक्षक, सभी जिलों के खेल अधिकारी एवं खेल संघों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में कॉन्क्लेव में शामिल हुए।

संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर भाजपा समरसता संकल्प अभियान चलाएगी: वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी द्वारा दिखाया गया मार्ग ही हमारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के संकल्प का मूल आधार है। उनके 650वें जयंती वर्ष पर चलने वाला समरसता संकल्प अभियान सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और विकसित भारत के निर्माण का व्यापक जनआंदोलन बनेगा।

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री वर्मा ने मंगलवार को यहाँ एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत पत्रकार वार्ता में बताया कि यह अभियान 29 जुलाई 2026 (आषाढ़ पूर्णिमा) से प्रारंभ होकर 20 फरवरी 2027 (माघ पूर्णिमा) तक पूरे देश में राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, मंडल एवं ग्राम स्तर पर व्यापक जनभागीदारी के साथ संचालित किया जाएगा।

अभियान का उद्देश्य संत गुरु रविदास महाराज के समता, सामाजिक न्याय, मानवता, सेवा, सद्भाव और सामाजिक समरसता के दिव्य संदेश को जन-जन तक पहुँचाना तथा विकसित भारत के निर्माण में समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित करना है। श्री वर्मा ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास केवल किसी एक समाज के संत नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के महान पथप्रदर्शक, भक्ति आंदोलन के महान संत, श्रेष्ठ समाज सुधारक और महान आध्यात्मिक चिंतक हैं, जिन्हें उनके समय के अनेक संतों तथा बाद की पीढ़ियों के संतों ने भी अत्यंत सम्मान दिया।

भूपेश सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार और लचर नीतियों की मिसाल रहा: अनुराग

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने कांग्रेस और पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान डिप्टी कलेक्टर और राज्य प्रशासनिक सेवा के अन्य उच्च पदों, जो कि पीएससी जैसी संस्थाओं के माध्यम से भरे जाते हैं, की खुलेआम नीलामी की गई। मेधावी और योग्य युवाओं के अधिकारों को दरकिनार कर पदों को बेचा गया। तत्कालीन सरकार के दौरान हुए बड़े पैमाने पर घोटालों का ही परिणाम है कि आज लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष सहित कई जिम्मेदार अधिकारी एवं व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे हैं।

गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष श्री सिंहदेव ने कहा कि एक ओर कांग्रेस और उसके नेता नैतिकता, भ्रष्टाचार-विरोध और पेपर लीक की बातें करते हैं, तो दूसरी ओर उनके अपने ही शासनकाल में हुए इन गंभीर घोटालों पर वे मौन साधे रहते हैं। तो अब कांग्रेस किस मुँह से पेपर लीक को लेकर मिथ्याचार का प्रदर्शन कर रही है? श्री सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस कितनी छात्र और युवा विरोधी है, यह पूरा प्रदेश भलीभाँति जानता है। कांग्रेस शासनकाल में तो पेपर लीक नहीं, पदों की नीलामी हुई थी! प्रदेश के युवाओं और अभ्यर्थी छात्रों के साथ भारी छल किया गया। पिछली सरकार का कार्यकाल केवल भ्रष्टाचार, पदों की नीलामी और जनविरोधी फैसलों के लिए याद किया जाएगा।गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष श्री सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस भ्रष्टाचार की जवाबदेही से बच नहीं सकते। यदि गांधी में यदि जरा भी शर्म और नैतिकता शेष है तो उन्हें भ्रष्ट आचरण में संलिप्त छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके साथ सरकार में प्रमुख पदों पर रहे नेता जैसे टी.एस. सिंहदेव समेत दीगर मंत्रियों व नेताओं, जिन्हें जनता ने तो चुनाव में पहले ही नकार दिया है, पर सख्त कार्रवाई करते हुए अब उन्हें पार्टी के पदों से भी हटाना चाहिए।

श्री सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश सरकार की नीतियों, घोटालों और छलावे को भली-भाँति समझकर उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। अब घड़ियाली आँसू बहाने से कांग्रेस का चरित्र बदलने वाला नहीं है।

केन्द्र और राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल: भूपेश बघेल

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य और केंद्र सरकार पर एक साथ तीखा हमला बोला है। उन्होंने खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, खाद की किल्लत और युवाओं पर कार्रवाई जैसे कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है।

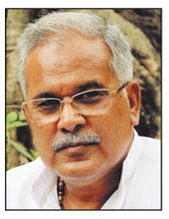

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में खंड वर्षा के कारण खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है, लेकिन किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि 16 जून से स्कूल खुल गए, लेकिन आज तक कई बच्चों को न तो बस्ता मिला है और न ही ड्रेस। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब भाजपा सरकार में वेस्ट इंडिया कंपनी बिजली में लुट मचाए हुए है, साय की योजना अडानी का स्मार्ट मीटर और उसमें अंबानी का चिप लगाकर संगठित लूट मचाए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार को 9 लाख का बिल इसी महीने थमाया गया है, गर्मी से ज्यादा बिल बरसात में आ रहे हैं, बिजली बिल की अधिक वसूली से हर वर्ग प्रभावित है, जन आक्रोश है, कवर्धा जिले के पांडातराई में आम जनता घरों, दुकानों और खेतों में जबरिया लगाए गए स्मार्ट मीटर को उखाड़कर फेक रहे प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं से अत्याचार के बाद अब मीटर रीडरों को भी निकलने की तैयारी है, वे भी आंदोलित हैं। स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ता परेशान हैं और मीटर रीडरों की नौकरियां भी खत्म हो गई हैं।

ढाई साल की सरकार में ही भाजपा में भगदड़, कार्यकर्ता नाराज पार्टी छोड़ रहे : बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ढाई साल में ही भाजपा सरकार के सारे दावे खोखले निकले भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता सरकार के क्रियाकलापों से बेहद खफा एवं नाराज है।

सरकार में बैठे नुमाइंदों के व्यवहार, कार्यकर्ताओं को सरकार में पद की उम्मीद नही करने की हिदायत एवं चंद लोग जो 15 साल के सत्ता के दौरान मलाई खाये वही लोगो को निगम मंडल आयोग में पुन: नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। भाजपा कार्यकर्ता भी सरकार की नाकामी उपेक्षा जनविरोधी रवैये से नाराज है। डोंगरगढ़ में भाजपा के 111 कार्यकर्ताओं ने पार्टी और सरकार की कार्यशैली से नाराज हो कर पार्टी छोड़ दिया। इसके पहले भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत एवं पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब भाजपा का अंतर्कलह खुलकर सामने आ रहा है। एल्डरमैन की नियुक्ति पैसा लेकर करने का आरोप भाजपा नेताओं पर लग रहा है। पूरा प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता से नाराज है। भाजपा कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़ना बताता है कि सरकार कितनी अलोकप्रिय हो चुकी है। सरकार जनता के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं का भी भरोसा खो चुकी है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी के गारंटी और साय के सुशासन पर भाजपा कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं रहा है। जिस प्रकार से प्रदेश की जनता से वादा किया गया और कार्यकर्ताओं ने उसे वादे को घर-घर तक पहुंचा था अब भाजपा के कार्यकर्ताओं को सरकार की नाकामी से दुख और पीड़ा हो रही है और आम जनता से नजर नहीं मिल पा रहे हैं इसलिए पार्टी छोड़कर जा रहे हैं ढाई साल में सरकार ने प्रदेश में हालत कर दिए हैं कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाने से डर रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ढाई साल की सरकार में कोई उपलब्धि नाम की चीज नहीं है जिसका बखान भाजपा के कार्यकर्ता कर सके और जिस प्रकार से महंगी बिजली, गरीबों के घर दुकान में तोड़फोड़ हो रहा है स्कूल बंद हो रही है वैध और अवैध शराब के चलते पूरा प्रदेश परेशान है। आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं इसे हर वर्ग दुखी है उसे भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल है और इस सरकार विदाई लगभग तय है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

आयुष शिविर में हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय आयुष कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सूरजपुर जिला के ग्राम रघुनाथपुर में ऑर्थ्रिटयो आर्थराइटिस एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर तथा वयोमित्र योजना के तहत निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया।शिविर में आयुष चिकित्सक डॉ. कीर्ति एवं श्री झूलसिंह कंवर (एमपीडब्ल्यू) ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं। विशेष रूप से हड्डी एवं जोड़ों के दर्द, गठिया, मांसपेशियों से संबंधित विकारों तथा वृद्धजनों की सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों का परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के साथ मरीजों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया गया तथा आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से योग, संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में ग्रामीणों को यह भी बताया गया कि बढ़ती उम्र में नियमित व्यायाम, उचित खानपान और समय पर स्वास्थ्य जांच से जोड़ों एवं मांसपेशियों संबंधी समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर प्रदेशभर में जागरूकता

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुदृढ़ और जनकेंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में निरंतर प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेशभर में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया। शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तथा सामुदायिक स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को हेपेटाइटिस बी एवं सी संक्रमण से बचाव, समय पर जांच, टीकाकरण तथा सुरक्षित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप प्रदेश में आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से निवारक स्वास्थ्य सेवाओं, समय पर रोगों की पहचान तथा जनजागरूकता को स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता बनाया गया है, जिससे गंभीर बीमारियों की रोकथाम एवं प्रभावी उपचार सुनिश्चित हो सके। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही सहित प्रदेश के सभी जिलों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में हेपेटाइटिस बी एवं सी की स्क्रीनिंग की गई तथा स्वास्थ्य कर्मियों एवं उच्च जोखिम वाले हितग्राहियों का हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण किया गया।

नाले पर निर्मित अवैध पाटों को जेसीबी से तोड़ा गया

रायपुर। नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे और आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम जोन 6 स्वास्थ्य विभाग द्वारा जोन क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 60 में भैरव नगर से बोरिया रोड तक नाले पर निर्मित लगभग 20 अवैध पाटों को जेसीबी मशीन की सहायता से तोड़कर नगर निगम जोन 6 जोन कमिश्नर हितेन्द्र यादव के मार्गनिर्देशन एवं वार्ड पार्षद रमेश सपहा एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी आदिव्य हजारी की उपस्थिति में पाटों के चलते नाला सफाई में आ रही बाधा को दूर करते हुए कब्जामुक्त करवाने के बाद नाले की सफाई करते हुए लगभग 3 डम्पर मलमा बाहर निकाला गया. बारिश में जलभराव की समस्या दूर करने प्रभावी कार्रवाई की गयी।

विकास का कोई विकल्प नहीं : मंत्री टंकराम वर्मा

रायपुर। जिले के तिल्दा विकासखंड अंतर्गत टंडवा गांव में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कुल 8.32 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस दौरान मंत्री वर्मा ने ग्राम टंडवा में 444.55 लाख रुपये की लागत से बनने वाली दैहानपारा से झोपड़ा पारा बैकुंठ सड़क (2.675 किमी) और 387.69 लाख रुपये की लागत वाली टंडवा से बैकुंठ सड़क (2.65 किमी) का भूमिपूजन किया। इसके साथ ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में 5 लाख रुपये के साइकिल स्टैंड और 10 लाख रुपये के प्रार्थना शेड का लोकार्पण भी संपन्न हुआ।

मंत्री वर्मा ने कहा कि ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की वर्षों पुरानी सड़क निर्माण की मांग अब पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में भी इस मार्ग को स्वीकृति दिलाई गई थी, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों के कारण काम रुक गया था। अब न केवल सड़क की स्वीकृति मिली, बल्कि बोनस के रूप में दो प्रमुख सड़कों की सौगात मिली है। इस मार्ग के बनने से विद्यार्थियों, कामगारों, दुकानदारों और आम जनता को आवागमन में समय की बचत होगी और बड़ी सुविधा मिलेगी।

बीरगांव ननि का सफाई अपनाओ-बीमारी भगाओ अभियान

रायपुर। नगर पालिक निगम बीरगांव में आयुक्त श्री युगल किशोर उर्वशा के निर्देशन में सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओअभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में एंटी लार्वा दवा एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने तथा जलजनित एवं मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के उद्देश्य से नालियों, जलभराव वाले स्थानों एवं अन्य चिन्हित क्षेत्रों में दवा का छिड़काव किया गया। नगर निगम की टीम द्वारा नागरिकों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने, पानी जमा न होने देने तथा साफ-सफाई के प्रति जागरूक रहने की अपील भी की गई। आयुक्त श्री युगल किशोर उर्वशा ने कहा कि बरसात के मौसम में मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा लगातार विशेष स्वच्छता एवं जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे निगम के स्वच्छता अभियान में सहयोग करते हुए अपने घर एवं आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखें।

मुख्यमंत्री साय ने नीट सफल विद्यार्थियों से किया आत्मीय संवाद

प्रतिभा किसी भी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित एकलव्य संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों से नीट-2026 में सफल विद्यार्थियों से आत्मीय चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने सभी विद्यार्थियों को उनकी उल्लेखनीय सफलता पर बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़, विशेषकर जनजातीय समाज के लिए गर्व का विषय है।

उन्होंने कहा कि एकलव्य विद्यालयों के विद्यार्थियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अवसर, संसाधन और संकल्प मिलने पर प्रतिभा किसी भी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आपके विद्यालय का नाम एकलव्य है और भारतीय इतिहास में एकलव्य का स्थान अद्वितीय है। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना आदर्श मानकर कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर साधना और समर्पण के बल पर धनुर्विद्या में असाधारण दक्षता प्राप्त की। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि उसी प्रकार आप भी अथक परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ निश्चय के साथ अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि सफलता का सबसे बड़ा मंत्र निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खूब पढ़िए, आगे बढ़िए और और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भागीदार बनिए।

मुख्यमंत्री साय ने विद्यार्थियों को संत कबीर के प्रसिद्ध दोहे गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूँ पाय; बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय का उल्लेख करते हुए गुरु के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गुरु ही हमें ज्ञान देकर जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने गुरुजनों का सदैव सम्मान करने और उनसे प्राप्त ज्ञान को समाज के हित में उपयोग करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा देशभर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लिए यह गर्व की बात है कि प्रदेश में एकलव्य विद्यालय संचालित हैं, जहां जनजातीय समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एकलव्य की तरह लक्ष्य साधिए, सफलता निश्चित मिलेगी। उन्होंने कहा कि नीट जैसी कठिन राष्ट्रीय परीक्षा में सफलता प्राप्त करना आपके परिश्रम, आपके माता-पिता के आशीर्वाद और गुरुजनों के समर्पण का परिणाम है। उन्होंने इस अवसर पर सभी अभिभावकों और शिक्षकों को भी बधाई दी।

वास्तविक शक्ति का आधार आंतरिक संतुलन और मानसिक सुदृढ़ता है: डॉ. गोयल

रायपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान में ब्रह्माकुमारीज़ के वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय अभियान इको केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत तनाव प्रबंधन एवं प्रकृति संरक्षण विषय पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारीज़ के वरिष्ठ राजयोगी एवं वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के दिल्ली जोनल कोऑर्डिनेटर डॉ. पीयूष गोयल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। अपने प्रेरणादायक एवं व्यावहारिक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि वास्तविक शक्ति का आधार आंतरिक संतुलन और मानसिक सुदृढ़ता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से सशक्त होता है, वही जीवन की चुनौतियों और बाहरी आपदाओं का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है।

तनाव प्रबंधन पर अपने विचार रखते हुए डॉ. गोयल ने प्रतिभागियों से अपनी क्षमताओं को पहचानने, स्वयं की सराहना करने तथा सदैव सकारात्मक सोच अपनाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि मन में शुद्ध एवं श्रेष्ठ विचारों का विकास मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे तनाव स्वत: कम होने लगता है और व्यक्ति संतुलित एवं सुखद जीवन जी सकता है।पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हुए उन्होंने प्रकृति को हमारी माँ के समान बताते हुए कहा कि इसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। उन्होंने सभी से-पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सिंगल-यूज़ प्लास्टिक का पूर्णत: बहिष्कार तथा जल संरक्षण के संकल्प लेने का आग्रह किया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.